

## My Notes.....

### राष्ट्रीय

#### भारत को उसका 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर मिला

यूनेस्को ने मुंबई की 'विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको' इमारतों को विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में शामिल किया। यूनेस्को के इस फैसले से वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का प्रभाव बढ़ना तय है। 'एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन ( विक्टोरिया टर्मिनस ) के बाद विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको' को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जाना मुंबई को मिला तीसरा ऐसा सम्मान है। एलिफेंटा गुफाओं को 1987 और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

#### क्या है

1. यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42 वें सत्र में यह फैसला किया गया। यह बैठक बहरीन के मनामा में चल रही है।
2. मुंबई के 'क्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको' को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नामांकित करने के प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज तैयार करने वाली संरक्षण वास्तुविद आभा नारायण लांबा ने कहा कि यह मुंबई और भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है।
3. ये इमारतें भव्य वास्तुकला शैलियों में बनी हैं। वे देश के एक जीवंत धरोहर और करीब दो सदियों में शहर के विकास के परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे वित्तीय शहर के तौर पर मशहूर मुंबई को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर प्रमुख जगह मिली है।
4. विश्व धरोहर समिति में सभी 21 देशों ने नामांकन का समर्थन किया जो बहुत दुर्लभ है। अजरबैजान ने इसे बेहतरीन दस्तावेज करार दिया और पर्यवेक्षक देश के रूप में फ्रांस ने इसे शानदार करार दिया।
5. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहा कि यूनेस्को के इस तमगे से देश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है जिनमें 29 सांस्कृतिक , सात प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल हैं।
6. दिल्ली की तरह अब मुंबई में भी तीन विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूँ का मकबरा विश्व धरोहर स्थल हैं।
7. पिछले साल गुजरात के अहमदाबाद को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था। अहमदाबाद विश्व धरोहर शहर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला शहर है।

#### आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी

नीति आयोग ने 31 मार्च, 2018 से 31 मई, 2018 के बीच जिलों के स्व-रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर आकांक्षी जिलों के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना के पाँच विकासात्मक क्षेत्रों में पहली डेल्टा रैंकिंग ( वृद्धिशील प्रगति ) शुरू की। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने चैम्पियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड को भरकर तत्क्षण डेटा उपलब्ध कराने में जिलों द्वारा प्रदर्शित गहरी दिलचस्पी पर प्रकाश डाला। इस रैंकिंग का उद्देश्य जिलों में गतिशील टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना

**पैदा करना है।** चूँकि इन जिलों में विरासत, अप्रयुक्त या कमजोर संसाधन आधार, कठोर जीवन परिस्थितियों आदि के कारण विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह रैंकिंग क्षेत्र और सूचक विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करने का भी एक साधन है ताकि टीम इंडिया जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है तत्काल सुधारात्मक उपाय कर सके।

**क्या है**

1. जिलों ने 01 अप्रैल, 2018 से चौपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड में डेटा दर्ज करना शुरू किया और कुल 112 में से 108 जिलों ने

इस रैंकिंग में भाग लिया। शेष चार जिलों द्वारा डेटा प्रविष्टि भी प्रगति पर है, हालांकि वे इस रैंकिंग का हिस्सा नहीं हैं।

2. अप्रैल और मई 2018 के दौरान किए गए संयुक्त सुधारों के लिए डेल्टा रैंकिंग की पारदर्शी तरीके से गणना की जाती है।

3. कुछ डेटा प्वाइंट केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त किए गए हैं जैसे कि वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत बुनियादी ढांचे के तीन संकेतक - घरेलू

#### फ्लैशबैक

1. इस साल जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, 'आकांक्षी जिलों के परिवर्तन' के कार्यक्रम का उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलना है।
2. कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं), सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी और जिलाधिकारी) और जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा है।
3. राज्य मुख्य वाहकों के रूप में हैं और यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करेगा, तत्काल सुधार के लिए बेहतर परिणाम देने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा, प्रगति को मापेगा और जिलों को रैंक देगा।
4. सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है - सबका साथ, सबका विकास।
5. उनकी क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए यह कार्यक्रम बढ़ती अर्थव्यवस्था में पूरी तरह भाग लेने की लोगों की क्षमता में सुधार करने पर बारीकी से नजर रखता है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और मूलभूत बुनियादी ढांचा इस कार्यक्रम के तहत विशेष ध्यान दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं।
6. विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद, जिलों की प्रगति को मापने के लिए 49 प्रमुख निष्पादन संकेतक चुने गए हैं। जिलों को अपने राज्य के भीतर सबसे अच्छे जिले के बराबर पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके और दूसरों से सीखकर, देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है।

विद्युत कनेक्शन, घरेलू शौचालय और ग्रामीण पेयजल। हालांकि, अधिकांश डेटा बिंदुओं को स्वयं विभिन्न जिलों द्वारा स्व-रिपोर्ट किया गया है।

4. तेलंगाना के आसिफाबाद जिले, जो इस साल मार्च में जारी बेसलाइन रैंकिंग में 100वें स्थान पर था, ने पिछले दो महीनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और डेल्टा रैंकिंग में 15वें स्थान पर आ गया है। गुजरात के दाहौद जिले ने 19.8 अंकों का सुधार करते हुए डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया (यह बेसलाइन रैंकिंग में 17वें स्थान पर था)।

5. सिक्किम का पश्चिम सिक्किम जिला 18.9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो बेसलाइन रैंकिंग में 30वें स्थान पर था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने भी 14.7 अंक सुधारकर डेल्टा रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि बेसलाइन रैंकिंग में यह 45वें स्थान पर था।
6. यह डेल्टा रैंकिंग एक कदम आगे ले जाती है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विशिष्ट पहलुओं को देखती है और विश्लेषण करती है कि जिलों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछले दो महीनों में कैसा प्रदर्शन किया है। यह समूहन और स्थिति जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों को इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और भविष्य में अपनी रैंकिंग में सुधार करने में सहायता करेगी।
7. नीति आयोग के ज्ञान भागीदारों - टाटा ट्रस्ट और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (आईडी इनसाइट्स) से 13 सर्वेक्षण संकेतकों पर डेटा उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है और उन्होंने 29 डेटा प्वाइंट्स के लिए मान वैधीकृत किए हैं। अगली रैंकिंग इन इनपुटों को ध्यान में रखेगी और इसके तुरंत बाद जारी की जाएगी।

### राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्र को समर्पित

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पठन-पाठन दिवस (19 जून 2018) के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लांच की। सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है।

#### क्या है

1. एनडीएल भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, वीडियो-आडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है।
2. इस डिजिटल लाइब्रेरी को देश के लिए समर्पित करने के साथ ही डिजिटल भारत के एक नये युग की शुरुआत हो गई है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। यह सेवा निःशुल्क है और 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
3. एनडीएलआई में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि प्रति वर्ष इस संख्या में 10 गुनी वृद्धि हो।
4. यह वेबसाइट के अलावा एनडीएल मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है। एनडीएलआई मोबाइल एप पूरे देश के पुस्तकालयों और यहां तक कि विदेशी पुस्तकालयों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है।
5. यह एप आईफोन और एंड्रायड दोनों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। उपयोगकर्ता विषय, स्रोत, सामग्री का प्रकार आदि के माध्यम से विषय वस्तु ढूंढ सकते हैं। अभी यह एप तीन भाषाओं में उपलब्ध है-अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला।
6. संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित होने वाले भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी भारत को विश्व स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम बनाएगी।

### नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल: 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक बार अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च 26,455 रुपये है। यह राशि प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से एक भारतीय व्यक्ति के तीन महीने की आमदनी के बराबर है। आंकड़ों पर गौर करें तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों की तुलना में असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इलाज कराना ज्यादा महंगा है।

**क्या है**

1. अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले मेडिकल एवं गैर-मेडिकल खर्च के ब्योरे के मुताबिक, देश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था वाले राज्यों में शुमार दिल्ली में आम धारणा के विपरीत अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च देश में सबसे कम 7,737 रुपये है। वहीं, असम में एक बार अस्पताल जाने का मतलब 52,368 रुपये का चूना लगना है।
2. हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो अस्पतालों में सबसे सस्ता इलाज उत्तर प्रदेश में होता है। यहां अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च 13,931 रुपये आता है। इसके बाद झारखंड (16,174 रुपये), मध्य प्रदेश (17,117 रुपये), छत्तीसगढ़ (24,891 रुपये), बिहार (28,058 रुपये), राजस्थान (31,978 रुपये) और हिमाचल प्रदेश (35,217 रुपये) का स्थान आता है।
3. खास बात ये है कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 75 फीसदी लोग अपनी घरेलू बचत से, 18 फीसदी लोग कर्ज लेकर चुकाते हैं। वहीं करीब 0.4 फीसदी लोगों को इलाज के खर्च के लिए अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ती है।
4. दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च सबसे कम होने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एम्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और जीबी पंत जैसे केंद्र और राज्य सरकार के बड़े अस्पतालों की मौजूदगी के चलते दिल्ली में बड़ी संख्या में मरीजों को नाममात्र की दर पर इलाज मिलता है। ऐसे में निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही अधिक वसूली के बावजूद औसत खर्च में यहां हॉस्पिटलाइजेशन सस्ता पड़ता है।

राज्य	औसत खर्च
असम	52,368
उत्तर प्रदेश	13,931
उत्तराखंड	33,402
बिहार	28,058
झारखंड	16,174
दिल्ली	7,737

## देशभर में मेट्रो चलाने को केंद्र ने बनाई समिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेट्रो रेल तंत्र के लिए मानदंड तय करने को एक समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि इस समिति के अध्यक्ष ई.श्रीधरन होंगे। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से रिटायर अधिकारी श्रीधरन 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। वह मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं।

**क्या है**

1. दिल्ली मेट्रो के मुंडका-बहादुरगढ़ रेलखंड का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता सुविधाजनक, आरामदेह और क्वालिटी शहरी परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना है।
2. हमारी सरकार मेट्रो के संबंध में एक नीति ले कर आई। दरअसल हमने महसूस किया कि मेट्रो प्रणाली से जुड़े पहलू के लिए बुनियादी मानकों के अनुरूप बेहतर तालमेल और काम की आवश्यकता है।
3. सरकार देश में मेट्रो कोच बनाकर 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना चाहती है। कई देशों ने दिल्ली मेट्रो और अन्य मेट्रो के निर्माण में हमारी मदद की। अब हम मेट्रो प्रणाली के लिए कोच की रूपरेखा बनाकर अन्य देशों की मदद कर रहे हैं।

4. प्रधानमंत्री ने कहा, मेट्रो प्रणाली की निर्माण प्रक्रिया सहकारी संघवाद से भी जुड़ी हुई है। भारत में जहां भी मेट्रो बनाया जा रहा है, केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों साथ मिलकर काम कर रही हैं। नए भारत को नए और स्मार्ट बुनियादी ढांचे की जरूरत है।

## UGC को खत्म कर उच्च शिक्षा आयोग की तैयारी

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने और फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने यूजीसी एक्ट में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत यूजीसी नाम की संस्था अब खत्म हो जाएगी। इसकी जगह एचईसीआई (हायर एजुकेशन कमीशन आफ इंडिया) लेगा। लेकिन इसके पास विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय मदद देने का अधिकार अब नहीं होगा। अब यह अधिकार सीधे मंत्रालय के पास होगा।

क्या है

1. नए एक्ट के तहत एचईसीआई के पास फर्जी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फर्जी डिग्री बांट रहे संस्थानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई और मान्यता रद्द करने तक का अधिकार होगा। साथ ही अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ जुर्माना और तीन साल की सजा का भी अधिकार होगा।
2. वहीं नए एक्ट के तहत सभी विवि के लिए एक ही आयोग होगा। इनमें केंद्रीय विवि, राज्य विवि, निजी विवि, डीम्ड विवि आएं। जिनके लिए वह नियम और दिशा-निर्देश तय कर सकेंगे।
3. अभी निजी और डीम्ड जैसे विश्वविद्यालयों के लिए नियम मंत्रालय से तय होते हैं। इसके साथ ही एचईसीआई के दायरे में ऑनलाइन रेगुलेशन, नैक को मजबूती देने, विवि और कालेजों को स्वायत्ता, स्वयं पोर्टल सहित ओपन लर्निंग रेगुलेशन आदि तय करने का भी काम होगा।
4. मौजूदा समय में मंत्रालय के पास विवि और कालेजों को ज्यादा ग्रांट देने और निरीक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि नए बदलाव के बाद गठित होने वाले एचईसीआई के पास वित्तीय अधिकार नहीं होगा।
5. उसका फोकस सिर्फ विश्वविद्यालयों के पठन-पाठन और शोध क्षेत्र में किए जा रहे उसके काम-काज को लेकर रहेगा। इसके अलावा मान्यता जैसे विषयों का निराकरण ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए एचईसीआई के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
6. नए एक्ट के तहत गठित होने वाले एचईसीआई में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 12 सदस्य भी होंगे। इसके साथ ही आयोग का एक सचिव भी होगा, जो सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा।
7. इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। चेयरमैन का चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एक चार सदस्यीय सर्च कमेटी करेगी। इनमें उच्च शिक्षा सचिव भी बतौर सदस्य शामिल होंगे।

## विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास का हुआ आगाज

अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में आयोजित किये जा रहे 26 देशों के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारत की ओर से भाग लेने के लिये भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री हवाई के निकट अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पहुंच चुका है। विश्व के इस सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक में 47 युद्धपोत, पांच पनडुब्बियां, दो सौ से अधिक विमान और 25 हजार नौसैनिक, 18 राष्ट्रीय थल सेना भाग ले रहे हैं। इस साल अभ्यास की थीम है सक्षम, अनुकूल और भागीदार।

क्या है

1. रिम ऑफ द पैसिफिक (रिमपैक) नाम का यह अभ्यास हर दो साल में आयोजित होता है जो आधिकारिक तौर पर 28 जून 2018 से शुरू हो गया है। पहली बार इस साझा अभ्यास में चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है।
2. गौरतलब है कि यह अभ्यास 1971 में शुरू हुआ था और तब इसमें अमेरिकी सैन्य खेमे के देश ही भाग लिया करते थे, लेकिन अब इसमें अमेरिका के गैर-सैनिक साथी देशों को भी आमंत्रित किया जाने लगा है। इस साल रिमपैक का यह 26 वां अभ्यास होगा।
3. इस अभ्यास में भारत और मेजबान अमेरिका के अलावा आस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रुनेई, कनाडा, कोलम्बिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वियतनाम और ब्रिटेन भाग ले रहे हैं।
4. अमेरिका के थर्ड फ्लीट पब्लिक अफेयर्स के मुताबिक रिमपैक में पहली बार वियतनाम, इजराइल, ब्राजील और श्रीलंका को आमंत्रित किया गया है। यह अभ्यास दो अगस्त तक चलेगा।
5. रिमपैक में चीन को नहीं आमंत्रित किये जाने के बारे में अमेरिकी नौसैनिक अधिकारियों का कहना है कि चीन को रिमपैक में भाग लेने के लिये दक्षिण चीन सागर में सभी कृत्रिम सुविधाओं बनाने की गतिविधियों को रोकना होगा। कृत्रिम द्वीपों से सभी हथियारों को हटाना होगा और इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में अपना योगदान करना होगा।

### एप 'रीयूनाईट' लांच

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल एप लांच किया। इस एप का नाम 'रीयूनाईट' है। यह एप भारत में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री महोदय ने इस एप को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' और 'कैपजेमिनी' की सराहना की।

क्या है

1. खोए हुए बच्चों को उनके मातापिता से मिलाने का यह प्रयास, तकनीक के सुंदर उपयोग को दर्शाता है। यह एप जीवन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।
2. इस एप के माध्यम से मातापिता बच्चों की तस्वीरें, बच्चों के विवरण जैसे नाम, पता, जन्म चिन्ह आदि अपलोड कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं तथा खोए बच्चों की पहचान कर सकते हैं।
3. खोए हुए बच्चों की पहचान करने के लिए एमेजरिकोगनिशन, वेब आधारित फेशियल रिगोगनिशन जैसी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। यह एप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।
4. बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। बीबीए ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।
5. यह आंदोलन 2006 के निठारी मामले से शुरू हुआ है। इस अवसर पर नोबल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक श्री कैलाश सत्यार्थी भी उपस्थित थे।

### पेरिस समझौते के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे कई देश

जलवायु परिवर्तन पर किए गए पेरिस समझौते के मानकों पर कई देश खरे नहीं उतर रहे हैं। इनमें भारत का नाम भी है। समझौते के तहत 2030 के लिए जो लक्ष्य तय किए थे, उनमें कई देश काफी पीछे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भविष्य के लिए खतरा बढ़ने के

आसार हैं। पर्यावरण में मौजूद कार्बन की परत अब बढ़ रही है। भारत समेत अन्य कई देशों को कोयले पर आधारित बिजली घरों को बंद करना पड़ेगा, तभी हालात में सुधार संभव है। यह रिपोर्ट वैसे तो अक्टूबर में पेश की जानी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट लीक हो गई।

क्या है

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात यही रहे तो 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगी। उस स्थिति में समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो सूखा व बाढ़ के हालात बनेंगे।
2. हमारे लिए यह काफी शर्मनाक होगा, क्योंकि हम अपनी पीढ़ी को एक ऐसा संसार देकर जाएंगे जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। भारत में यह चीजें पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए उसे काफी सतर्क रहना होगा।
3. ग्लोबल लीड ऑन क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड के हरजीत सिंह कहते हैं कि भारत जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। उसे खास एहतियात बरतनी होंगी।
4. भारत की आधे से ज्यादा आबादी कृषि जैसे व्यवसाय पर निर्भर करती है। जलवायु में बदलाव होने से सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही उठाना होगा।
5. पेरिस समझौते में भारत समेत कई विकासशील देशों से अनुरोध किया गया है कि वो कार्बन के उत्सर्जन को 2030 तक 33 से 35 फीसद कम करें। इसके लिए सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों को लगाना होगा। कोयले से चलने वाले संयंत्र बंद करने होंगे।
6. रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई है कि ब्रिटेन भी कोयला के उपयोग को कम करने के मामले में शिथिलता बरत रहा है। उसे अपने उन प्रयासों में तेजी लानी होगी, जिससे कोयले पर आधारित संयंत्र खत्म किए जा सकें।
7. गौरतलब है कि अमेरिका इस समझौते से बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा की नीति से किनारा कर इससे अमेरिका को बाहर कर लिया था।

देश में पहला कार्बन फाइबर

यूनिट

मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) देश के पहले कार्बन फाइबर यूनिट में बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है। आरआइएल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि वह एयरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए कार्बन फाइबर यूनिट की स्थापना करेगी। दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कंप्लैक्स की मालिक आरआइएल इस कार्बन फाइबर यूनिट के जरिये मॉड्यूलर टॉयलेट, घर और पवन-चक्की के ब्लेड समेत कम

क्या होते हैं कंपोजिट प्रोडक्ट्स

1. कंपोजिट्स मुख्य तौर पर भौतिक या रासायनिक आधार पर दो बिल्कुल विपरीत गुणों वाली वस्तुओं को इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से मिलाकर विकसित किए गए उत्पाद होते हैं।
2. मौजूदा दौर में इनका सबसे सामान्य उदाहरण कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर का निर्माण रेयॉन, पिच या अन्य तरह की फाइबर छड़ों को बेहद उच्च तापमान से गुजारा जाता है।
3. इससे निकले उत्पाद को धागों की शकल दी जाती है और उन्हें रेजिन या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर चादर की शकल में बुना जाता है। उससे कई अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। बेहद कम वजन के साथ स्टील के समान या उससे भी ज्यादा ताकत का वहन करना कंपोजिट्स की बड़ी खासियतों में एक है।
4. इसके अलावा वे मौसम की मार भी आसानी से झेल सकते हैं। उन्हें किसी भी शकल में ढाला जा सकता है और उनमें क्षरण की भी संभावना नहीं होती है।

दाम और बड़ी मांग वाले उत्पादों का उत्पादन करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपोजिट्स क्षेत्र के लिए लांच की गई नई कंपनी रिलायंस कंपोजिट्स सॉल्यूशंस (आरसीएस) के माध्यम से आरआइएल देश की सबसे बड़ी कंपोजिट्स कंपनी बनने का लक्ष्य रख रही है।

क्या है

1. कंपनी ग्राफीन, विशिष्ट प्लास्टिक और इलास्टोमर तथा फाइबर री-इनफोर्ड प्रोडक्ट के उत्पादन की योजना बना रही है। ये सभी उत्पाद आने वाले दिनों में स्टील की जगह ले सकते हैं।
2. कंपनी का कहना है कि कार्बन फाइबर यूनिट के उत्पाद स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को मदद देने के अलावा आपदा प्रबंधन और सरकार की 'सबके लिए आवास' योजना के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होंगे।
3. रिपोर्ट में कंपनी ने कहा, 'आरआइएल खुद की तकनीक के जरिये देश की एयरोस्पेस और रक्षा समेत विशिष्ट औद्योगिक जरूरतों के लिए कार्बन फाइबर उत्पादों में बड़े निवेश की योजना बना रही है।
4. गौरतलब है कि आरआइएल ने कंपोजिट्स कारोबार में प्रवेश के लिए पिछले वर्ष केमराॅक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। उसके बाद से कंपनी ग्लास और कार्बन फाइबर री-इनफोर्ड पॉलिमर जैसे थर्मोसेट कंपोजिट्स पर फोकस कर रही है।

### नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जून 2018 नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक में समापन टिप्पणियां कीं। प्रधानमंत्री ने रचनात्मक विचार विमर्श एवं विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए उपस्थित समूह को आश्चस्त किया कि निर्णय-निर्माण करते समय इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने नीति आयोग से कहा कि वह तीन महीनों के भीतर सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिन्दुओं पर राज्यों के साथ अनुवर्ती कदम उठाए।

क्या है

1. नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 आकांक्षापूर्ण जिलों की तर्ज पर, राज्य आकांक्षापूर्ण ब्लॉक के रूप में राज्य के कुल ब्लॉक के 20 प्रतिशत को चिन्हित करने के लिए अपने खुद के मानकों को निर्धारित कर सकते हैं।
2. मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए पर्यावरण के मुद्दे पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से उनके सरकारी भवनों, कार्यालय निवासों एवं स्ट्रीटलाइटों में एलईडी बल्ब का उपयोग करने का अनुरोध किया।
3. उन्होंने विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा जल संरक्षण, कृषि, मनरेगा आदि मसलों पर दिए गए कई अन्य सुझावों की सराहना की।
4. मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बुवाई-पूर्व एवं कटाई-उपरांत, दोनों ही चरणों समेत 'कृषि एवं मनरेगा' के दो विषयों के प्रति एक समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण पर अनुशासन करने के लिए एक साथ मिल कर कार्य करने की अपील की।
5. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी गांवों तक अब बिजली पहुंच चुकी है और सौभाग्या योजना के तहत अब 4 करोड़ घरों तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज चार वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो 40 प्रतिशत से भी कम था।

### 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) रिपोर्ट जारी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) रिपोर्ट जारी की। कार्यक्रम में श्री चौबे ने कहा कि देश में 2013 से मातृ मृत्यु



दर (एमएमआर) में रिकॉर्ड 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। एसआरएस के पहले के राउंड्स के अनुसार पहले के वर्षों में एमएमआर में हुई कमी की तुलना में यह अब तक की सबसे अधिक कमी है। श्री चौबे ने कहा, 'देश में मातृ मृत्यु दर 2011-13 में 167 थी, जो 2013-16 में घटकर 130 हो गयी। यह मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है।

क्या है

1. राज्यों में 60 से 70 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्य एनएचएम के जरिये किया गया है। एनएचएम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश को स्वस्थ और रोगमुक्त बनाना है। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की सुदृढ़ प्रणाली के कारण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार हुआ है।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य और उप जिला स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी एनएचएम की गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इससे इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ सके।
3. एनएचएम एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा है, क्योंकि यह राज्य में मौजूद सरकारी संरचनाओं, विभिन्न कार्य परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को आत्मसात करने में मदद करता है। साझा स्वास्थ्य लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए एनएचएम राज्यों को बहु-क्षेत्रीय लचीलापन और अभिसरण प्रदान करता है।
4. मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी-एचएचसी) के रूप में मजबूत किया है, ताकि 2022 तक 1,50,000 एचडब्ल्यूसी परिचालित करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।
5. एचडब्ल्यूसी में मध्य स्तर प्रदाता महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। हमें उन्हें प्रशिक्षण देने और उनकी दक्षताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एनएमसी विधेयक से राज्यों में लोगों को नौकरी पर रखने में लचीलापन आएगा।
6. सूक्ष्मजीव रोधी प्रतिरोधकता (एमआर) विशेषरूप से एसएनसीयू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुष्ठ रोग और कालाजार से प्रभावित जिलों के लिए समय सीमाबद्ध विशिष्ट रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
7. 11वीं सीआरएम टीम ने 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया, जिनमें से 4 पूर्वोत्तर के राज्य, 6 उच्च ध्यान केंद्रित राज्य और 6 गैर उच्च ध्यान केंद्रित राज्य थे।

## अन्तरराष्ट्रीय

### अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् से बाहर हुआ

अमेरिका ने 19 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) से बाहर होने का ऐलान कर दिया। यूएन में अमेरिका की अम्बेस्डर निकी हेली ने परिषद् पर इजरायल के खिलाफ राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया। हेली ने कहा कि रूस, चीन, क्यूबा और मिस्र जैसे देशों ने उसकी परिषद् में सुधार करने की कोशिशों में भी रोड़ा अटकाया। अमेरिका लंबे समय से 47 सदस्यीय इस परिषद् में सुधार की मांग कर रहा था।

क्या है

1. अमेरिकी रक्षा विभाग से किए गए ऐलान में हेली के साथ देश के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। हेली ने परिषद् पर असल में मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले देशों का बचाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मानवाधिकार का दुरुपयोग करने वाले अपना काम करते रहेंगे और परिषद् में चुने भी जाते रहेंगे।

2. चीन, क्यूबा, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों का हवाला देते हुए हेली ने कहा कि परिषद में कई ऐसे सदस्य हैं जो अपने नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार की भी इज्जत नहीं करते, लेकिन परिषद् लगातार उन देशों को बलि का बकरा बनाता है जिनका मानवाधिकार के मामले में रिकॉर्ड बेहतर है, ताकि वो इसे तोड़ने वालों से दुनिया का ध्यान हटा सके।
3. ट्रम्प प्रशासन का ये फैसला यूएन ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें मैक्सिको बार्डर पर माता-पिता के बच्चों से अलग होने को हद से ज्यादा गलत कदम बताया गया था। कई मानवाधिकार संगठन ट्रम्प प्रशासन पर मानवाधिकार को विदेश नीतियों में शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हैं।
4. अमेरिका तीन साल के लिए इस 47 सदस्यीय परिषद् का सदस्य था। हालांकि, उसका डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था।
5. पेरिस जलवायु और ईरान परमाणु समझौते के बाद ये तीसरा मौका है जब अमेरिका ने खुद को किसी बहुपक्षीय समझौते से अलग कर लिया है।
6. अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के शासन काल में भी तीन साल तक मानवाधिकार परिषद् का बहिष्कार किया था, लेकिन ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2009 में वह इस परिषद में फिर से शामिल हुआ था।

## SCO में पहली बार योग को मिली जगह

शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) में पहली बार योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही चीन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था।

क्या है

1. चीन में लोग योग को काफी पसंद करते हैं। यहां प्रत्येक साल योग दिवस का आयोजन किया जाता है। हालांकि एससीओ मुख्यालय में पहली बार योग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2. एससीओ के महासचिव राशिद अलीमोव के अलावा इस कार्यक्रम में चीन में भारत के राजदूत गौतम बम्बावले, उनकी पत्नी अमिता बम्बावले और कई देशों के राजदूतों सहित चीन में योग को पसंद करनेवाले लोगों ने हिस्सा लिया।
3. एससीओ में चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। इस संगठन में भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पिछले बार ही शामिल हुए हैं।

## अंतरिक्ष में बने देश असगार्दिया के मुखिया ने ली शपथ

अंतरिक्ष में बने दुनिया के पहले देश असगार्दिया का मुखिया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में चुन लिया गया। इस देश के पहले प्रमुख बनने का सौभाग्य रूसी वैज्ञानिक, अरबपति और समाज सेवी इगोर आशुबेत्ली को मिला है। इगोर के शपथग्रहण समारोह में दुनिया के कई देशों के राजनयिक, शोधकर्ता, इंजीनियर और विधि विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इगोर ने अपने वियना के हॉफबर्ग पैलेस में हुए शपथग्रहण समारोह में अपने देश के लिए अगले 25 साल में हासिल करने वाले लक्ष्य निर्धारित कर दिए। उन्होंने कहा कि उनका देश धरती की निचली कक्षा में पूरी तरह से बसने योग्य स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर स्थायी ठिकाने का भी निर्माण करेगा।

### क्या है

1. इगोर ने कहा कि हमने एक देश की सभी शाखाएं स्थापित कर ली हैं। अब मैं असगार्दिया के जन्म की घोषणा कर सकता हूँ। असगार्दिया का नाम नॉर्वे में प्रचलित पौराणिक कथाओं में बताए गए आसमान में बसे शहर असगार्द के नाम पर रखा गया है।
2. पौराणिक कहानी में इस देश को देवताओं का घर बताया गया है। इसकी स्थापना इगोर और कई अन्य अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने अक्टूबर 2016 में की थी। इसका मकसद धरती के बाहर एक ऐसे आजाद देश की स्थापना करना था, जिसमें लोग बिना जाति, धर्म, स्थान, उम्र, लिंगभेद और देश के भेदभाव के रह सकें।
3. अंतरराष्ट्रीय बाहरी अंतरिक्ष ट्रीटी के मुताबिक सरकारें अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों के निरीक्षण और उसके लिए अनुमति देने के लिए जिम्मेदार होंगी। इसमें व्यावसायिक और गैर लाभकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियां भी शामिल होंगी।
4. असगार्दिया के संस्थापकों को उम्मीद है कि उन्हें यहां धरती की तरह लगाए जाने वाले सख्त प्रतिबंधों का पालन नहीं करना होगा। इगोर ने कहा कि बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी तरह की खोज इनसान का अधिकार है और यह अधिकार धरती के किसी देश के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। इगोर यूनेस्को कमिशन ऑन स्पेस साइंस के अध्यक्ष भी हैं।

### हर एक बात बेहद खास

1. असगार्दिया 1 सैटेलाइट दिसंबर 2017 में लांच की गई
2. असगार्दिया का अपना संविधान, झंडा और राष्ट्रगान है
3. यह अपने केंद्रीय बैंक की स्थापना और सोलर नाम की क्रिप्टोकॉरेंसी बना लेगा
4. जल्द ही यह यूनाइटेड नेशन्स में सदस्यता के लिए आवेदन करेगा
5. दुनियाभर से लोगों को इस देश की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है
6. अभी दो लाख लोगों ने ऑनलाइन नागरिकता के लिए दिलचस्पी दिखाई है
7. असगार्दिया ने हाल ही में संसदीय चुनाव संपन्न कराए हैं, जिसमें 140 सदस्य चुने गए हैं
8. असगार्दिया का अपना मूलभूत ढांचा होगा, जो धरती से अलग होगा
9. असगार्दियन के पास हाथ में रखने वाले उपकरण होंगे, जिनमें उनका पासपोर्ट, क्रेडिटकार्ड और अन्य दस्तावेज होंगे

### सेशेल्स बना नया पड़ोस

सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर की हालिया भारत यात्रा के दौरान एजंप्शन द्वीप पर दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर नौसैनिक अड्डा बनाने पर सहमति बन ही गई, जिसे लेकर बीते लगभग एक महीने से आशंकाएं जताई जा रही थीं। भारत के लिए यह सामरिक लिहाज से बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चीन लगातार अपनी पैठ हिंद महासागर के द्वीपों में बना रहा है और यह भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों सेशेल्स में विपक्षी दलों ने भारत को लेकर जो विरोध किया था, उसमें चीन का अहम किरदार था। बड़ी उपलब्धि इसलिए भी कि यदि भारत सेशेल्स को राजी नहीं कर पाता तो एजंप्शन द्वीप में चीन या फिर कोई यूरोपीय देश, मसलन फ्रांस नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिशें करता और हिंद महासागर में चीन के इस तरह सैन्य विस्तार का मतलब है, भारत के लिए चुनौतियों व खतरों का बढ़ना। पर भारत बाजी पलटने में कामयाब रहा।

### क्या है

1. सेशेल्स के साथ दोस्ती अथवा सामरिक साझेदारी का नया युग सही अर्थों में वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा से शुरू हुआ।
2. उसी यात्रा के दौरान सेशेल्स के एजंप्शन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। मोदी की वह सेशेल्स यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 34 वर्षों के बाद की गई यात्रा थी। इसका तात्पर्य है कि बीते साढ़े तीन दशक में भारत ने हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की ओर ठीक से देखा ही नहीं। स्वाभाविक है कि भारतीय सामरिक नीति हिंद महासागर के द्वीपीय या छोटे देशों की महत्ता का आकलन भी नहीं कर पाई होगी।
3. लगभग 84 हजार की आबादी वाला सेशेल्स भले ही एक बहुत छोटा देश हो, किंतु भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सेशेल्स के साथ भारत का प्रमुख मुद्दा रक्षा और सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी है, जिसे सुदृढ़ करना भारत की प्राथमिकता है।
4. इस क्षेत्र में समुद्री दस्युओं के आधिक्य को देखते हुए भारत सेशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्स (एसपीडीएफ) की क्षमता मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है। सेशेल्स का जल सीमा क्षेत्र 1.3 मिलियन वर्ग किमी से भी ज्यादा विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन- ईईजेड) भी रखता है, इसलिए भारत ने उसकी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए उसे नौसैनिक जहाज आइएनएस तरासा दिया, जो सेशेल्स कोस्ट गार्ड के बेड़े में पीएस कांस्टैंट के नाम से शामिल हो चुका है।
5. इससे पहले सेशेल्स को पीएस टोपाज नाम जहाज दिया गया था। यही नहीं, 2013 में भारत ने सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की आतंकवाद और समुद्री दस्युओं से रक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक डोर्नियर-228 (समुद्री गस्ती विमान) भी भेंट किया था।
6. यही सेशेल्स की वायुसेना की सामुद्रिक क्षमता का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान उसे डोर्नियर लड़ाकू विमान देने और द्विपक्षीय सहयोग के प्रतीक के रूप में तटीय निगरानी रडार परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी।
7. तटीय निगरानी रडार परियोजना एजंप्शन द्वीप पर है, जो उन 115 द्वीपों में से एक है, जिससे मिलकर सेशेल्स बना है। दरअसल भारत के लिए सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में एक ग्रेट गेम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है।

#### हिंद महासागर नीति

1. अमेरिका पहले से ही अपनी हिंद महासागर नीति पर काम कर रहा है और अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेटकॉम) के अधीन त्वरित बल सक्रिय हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का हवाई व नौसैनिक अड्डा डिएंगो-गार्सिया, हिंद महासागर में भू-सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है।
2. दूसरी तरफ चीन हिंद महासागर में एक बड़ा संजाल निर्मित कर चुका है। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ प्लर्स के तहत ग्वादर (पाकिस्तान), मारओ (मालदीव), हंबनटोटा (श्रीलंका) से लेकर सिंहनौक्विले (कंबोडिया) जैसे बंदरगाहों के जरिये सामरिक-आर्थिक महत्व के मोतियों की पूरी शृंखला निर्मित कर चुका है।
3. पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भू-सामरिक दृष्टि से चीन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन मध्य-एशिया और इसके आस-पास के समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत प्रदर्शित कर सकता है।

## दक्षिण कोरिया, अमेरिका ने सैन्य अभ्यास निलंबन की पुष्टि की

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच पहले से तय सैन्य अभ्यास के निलंबन की पुष्टि कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सिंगापुर में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग-उन के साथ हुई शिखर बैठक में इस आशय की घोषणा की थी। उत्तर कोरिया से सुरक्षा के लिए दक्षिण कोरिया में बड़ी संख्या में अमेरिका सैनिक मौजूद हैं।

क्या है

1. जोंग का कहना है कि सैन्य अभ्यास के निलंबन से अगस्त में होने वाला उल्ची फ्रीडम गार्डियन सैन्य अभ्यास प्रभावित होगा।
2. दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका भविष्य की रणनीति पर चर्चा जारी रखेंगे। अन्य सैन्य अभ्यासों के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
3. उल्ची फ्रीडम गार्डियन सैन्य अभ्यास में करीब 17,500 अमेरिकी सैनिक हिस्सा लेने वाले थे। पेंटागन की प्रवक्ता डाना वाइट ने निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा, 'हम अतिरिक्त कार्रवाई पर समन्वय कर रहे हैं।'
4. अन्य सैन्य अभ्यासों पर अभी तक फिर से फैसला लिया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस का कहना है कि कोरियाई प्रायद्वीप से बाहर प्रशांत सैन्य अभ्यासों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
5. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मैटिस, विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन इस हफ्ते पेंटागन में मिलेंगे।

## अति अमीरों की संख्या बढ़ने के मामले में भारत आगे

भारत में बीते साल अति अमीरों की संख्या में 20 फीसदी की वृद्धि हुई। इस दौरान इनकी संपत्ति में भी जबर्दस्त उछाल आया। अति अमीरों की तादाद बढ़ने के मामले में भारत सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है। फ्रांसीसी टेक फर्म केपजेमिनी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में भारत में अति अमीरों की संख्या 20.4 फीसदी बढ़कर 2.63 लाख पर पहुंच गई। वहीं इस दौरान उनकी कुल संपत्ति 21 फीसदी बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर (डॉलर की वर्तमान दर से 68 लाख करोड़ रुपये से अधिक) पर पहुंच गई। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक तिहाई के बराबर है। 2017 में अमीरों की संख्या बढ़ने के मामले में भारत की दर सबसे तेज रही।

क्या है

1. बीते साल ग्लोबल स्तर पर अमीरों की संख्या में औसतन 11.2 फीसदी की और उनकी कुल संपत्ति में 12 फीसदी की वृद्धि हुई है।
2. अति अमीर की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है, जिनकी कुल निवेश योग्य संपत्ति 10 लाख डॉलर (डॉलर की वर्तमान दर से करीब 6.8 करोड़ रुपये) से ज्यादा होती है।
3. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन इस मामले में सबसे आगे हैं। 2017 में आए उछाल के बाद भारत इस मामले में 11वें स्थान पर पहुंच गया है।
4. भारत में अति अमीरों की संख्या में बढ़ोतरी में बीते साल बाजार पूंजीकरण में आए 50 फीसदी से ज्यादा के उछाल की अहम भूमिका रही।
5. इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष में रियल्टी सेक्टर में कीमतों में 4.8 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.7 फीसदी की दर से वृद्धि हुई। इस मामले में भी भारत वैश्विक औसत से आगे रहा।

6. रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से संपत्ति पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन यह अस्थायी था। इसके अलावा स्थिर मौद्रिक नीति, नोटबंदी का असर खत्म होने और बचत की ओर रुख करने से लोगों को संपत्ति बढ़ाने में मदद मिली।
7. गौरतलब है कि जनवरी में अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूह ऑक्सफेम ने देश में संपत्ति के बंटवारे पर रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी में से ऊपर के एक फीसदी लोगों का कब्जा 2017 में सृजित कुल संपत्ति के 73 फीसदी हिस्से पर था।
8. वहीं दूसरी ओर, 67 करोड़ लोगों यानी देश की आधी आबादी के पास केवल एक फीसदी संपत्ति थी। ऐसी स्थिति में अति अमीरों की बढ़ती संख्या और गरीबों की स्थिति जस की तस बनी रहने को लेकर सरकारों की नीतियां अक्सर सवालियों के घेरे में रहती हैं।

### नेपाल, चीन ने 8 समझौते किए

नेपाल और चीन ने 20 जून 2018 को 2.24 अरब डॉलर यानी 152 अरब रुपये के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी शर्मा ओली के चीन दौरे के दूसरे दिन यह समझौते हुए। ये समझौते दोनों सरकारों और निजी क्षेत्रों के बीच हुए, जहां चीनी निवेशक पनबिजली परियोजनाओं, जल संसाधनों, सीमेंट कारखानों और फलों की खेती और कृषि में निवेश करेंगे।

क्या है

1. समझौते नेपाल के दूतावास में हुए। ओली और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद अतिरिक्त समझौता ज्ञापन (एमयू) पर हस्ताक्षर होंगे।
2. फरवरी में सत्तासीन होने के बाद ओली का यह पहला चीन का आधिकारिक दौरा है।
3. ओली 19 जून से 24 जून तक के लिए चीन की यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा के दौरान बेल्ट एंड रोड पहल के तहत कई प्रॉजेक्ट्स और पेइचिंग की भारत-नेपाल-चीन आर्थिक गलियारे की योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।
4. बता दें, साल 2016 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में ओली ने चीन और नेपाल के संबंधों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने उस समय मधेशी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वक्त भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन के साथ ट्रांजिट व्यापार संधि भी की थी।

### एर्दोगन दूसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बने

तुर्की के राष्ट्रपति रोसेप तैय्यप एर्दोगन 24 जून 2018 को हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। इसके साथ ही वे दूसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बनेंगे। एर्दोगन को अब तक हुई 97.7 फीसदी मतगणना में 52.54 फीसदी वोट मिले। जबकि विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के उम्मीदवार मुहम्मद इन्जे को 30.68 फीसदी वोट मिले। इसके अलावा तुर्की में प्रधानमंत्री पद खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ही अब कैबिनेट की नियुक्ति करेंगे।

क्या है

1. मतगणना को लेकर विपक्ष शिकायत कर रहा है लेकिन इसके साथ ही सत्ता पर एर्दोगन की पकड़ मजबूत हो गई है। गौरतलब है कि 15 वर्ष से वे ही सत्ता पर काबिज हैं।

2. एर्दोगन 2014 में तुर्की का राष्ट्रपति बनने से पहले 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 2017 में हुए जनमत संग्रह में नए संविधान पर सहमति बनी थी। इस्तांबुल के अपने आवास से विजयी संदेश में एर्दोगन ने कहा कि मुझ पर देश ने भरोसा जताते हुए राष्ट्रपति पद का कार्य और कर्तव्य सौंपे हैं।
3. उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रपति प्रणाली को तेजी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 88 फीसदी मतदान कर तुर्की के लोगों ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। वही विपक्षी पार्टी ने कहा कि नतीजे कुछ भी रहें, वे लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।
4. तुर्की में पहली बार राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू की गई है जिसमें एर्दोगन के पास पहले से कहीं ज्यादा शक्तियां होंगी।
5. सरकारी और निजी संस्थाओं पर नजर रखने वाली संस्था स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड को प्रशासनिक जांच शुरू करने का अधिकार होगा। यह बोर्ड राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में, सैन्य बलों समेत बहुत सारे समूह सीधे तौर पर राष्ट्रपति के अधीन होंगे।

### भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की 15वीं बैठक 25 जून, 2018 को केनबरा, ऑस्ट्रेलिया में हुई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री श्री स्टीवन सिओबो ने की। संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक चार वर्ष के अंतराल के बाद सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई। मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि करने की जरूरत पर बल दिया। इस संबंध में दोनों ही देशों ने व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंडिया के बीच द्विपक्षीय विनिवेश को गति देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए।

क्या है

1. हाल ही में भारत में हुए बड़े सुधारों के बारे में भी निवेशकों को जानकारी दी। वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने वस्तु एव सेवा कर, अनौपचारिक क्षेत्र के संसाधनों को वित्तीय समावेशन के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित करने और भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर में निजी क्षेत्र का सराहनीय योगदान है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सुपर फंड्स को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
2. श्री प्रभु ने औद्योगिक गलियारे, बंदरगाह, स्मार्ट सिटी, हवाई अड्डे और रेल से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश के अवसरों के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी दी।
3. श्री सुरेश प्रभु ने 'लीडर्स ऑन एशिया' को एशिया सोसाएटी ऑस्ट्रेलिया में भारत की विकास गाथा ऑस्ट्रेलिया के अवसर विषय पर आयोजित समारोह को संबोधित किया।
4. इस अवसर पर बड़ी संख्या में अकादमिक क्षेत्र, सरकारी और व्यापार जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ज्ञान आधारित कृषि, सेवाओं, शिक्षा और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक साझेदार हैं।
5. चर्चा के दौरान श्री प्रभु ने भारत में हुए बड़े सुधारों के बारे में जानकारी दी और भारतीय समुदाय द्वारा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि भारत में भी उनके योगदान के लिए सराहना की। अपनी सफल यात्रा के दौरान श्री प्रभु ने सरकार, उद्यम और अन्य क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की। सभी बैठकें सद्भावपूर्ण माहौल में संपन्न हुईं।

## एफएटीएफ की निगरानी सूची में पाकिस्तान

आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान को एफएटीएफ की निगरानी सूची में लंबे समय के लिए शामिल कर दिया गया है। पेरिस में चल रही एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान की ओर से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सूची पेश की गई, लेकिन सदस्य देशों ने इसे नाकाफी करार दिया। फरवरी की बैठक में तीन महीने के लिए निगरानी सूची शामिल करते हुए आतंकी फंडिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की चेतावनी दी गई थी। क्या है

1. सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन और सउदी अरब ने भी आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है।
2. वैसे तो एफएटीएफ को किसी भी देश के साथ आर्थिक लेन-देन प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन निगरानी सूची में आने के बाद आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी कर्जा लेना कठिन हो जाएगा। कर्ज मिलेगा भी तो काफी महंगा मिलेगा।
3. बहुराष्ट्रीय कंपनियां पाकिस्तान में या वहां की कंपनियों से कारोबार करने से हिचकेंगी। यही नहीं, आतंकवाद को लेकर संवेदनशील देश इसके आधार पर पाकिस्तान के साथ आर्थिक लेन-देन रोक भी सकते हैं।
4. दरअसल पाकिस्तान लंबे समय तक दुनिया को दिखाने की कोशिश करता रहा है कि वह खुद आतंकवाद से पीड़ित है और उसे खत्म करने के लिए सारे प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत ने अक्टूबर 2016 में एफएटीएफ में पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को हो रही भारी फंडिंग का मुद्दा उठाया था।
5. भारत का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ से अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों की सूची में डाले गए लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उत-दावा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और आतंकी हमलों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए भारत ने कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे।
6. भारत के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एफएटीएफ ने इसकी जांच का फैसला किया और एशिया पैसिफिक ग्रुप को इस पर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन एशिया पैसिफिक ग्रुप के सदस्यों को पाकिस्तान प्रभावित करने में सफल रहा है और रिपोर्ट तैयार नहीं होने दी।
7. भारत ने फरवरी 2017 में एफएटीएफ की बैठक में फिर यह मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस मुद्दे को तकनीकी पहलुओं में उलझा दिया जाए। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के भारत के प्रस्ताव पर मिले समर्थन से पाकिस्तान की मंशा सफल नहीं हो सकी।

## अर्थशास्त्र

### ED पद पर नियुक्ति के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सुझाए नाम

बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने सरकारी बैंकों में एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (ईडी) के पद पर नियुक्ति के लिए 22 नामों की सिफारिश की है। बीबीबी, उच्च स्तरीय बोर्ड नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सरकार की ओर से गठित एक सलाहकार निकाय है। बीबीबी की ओर से शुरू किया गया यह पहला अहम अभियान है जिसका नेतृत्व नव नियुक्त अध्यक्ष बीपी शर्मा कर रहे हैं, जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव हैं। पूर्व सीएजी विनोद राय के दो वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद शर्मा को बीते अप्रैल महीने में ही इस पैनल का मुखिया बना दिया गया था।



### क्या है

1. बीबीबी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस पैनल के चेयरमैन और सदस्यों ने सरकार को भारत के उन 22 जनरल मैनेजरो के बारे में सुझाव दिया है जिन्हें सरकारी बैंकों में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है।
2. इस पैनल ने जिन जनरल मैनेजरो के नाम सुझाए हैं, उनमें मानस रंजन बिस्वाल, गोपाल गुप्ते, विवेक झा, आलोक श्रीवास्तव, हेमंत कुमार टम्टा, अजीत कुमार दास, अज्ञेय कुमार आजाद, दिनेश कुमार गर्ग, संजय अग्रवाल और शांति लाल के नाम शामिल हैं।
3. इन पदों पर नियुक्ति के बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट लेगी। गौरतलब है कि बैंकों में इस साल कुछ प्रमुखों के पद खाली हो रहे हैं।

### आर्थिक धोखाधड़ी पर रिपोर्ट

ग्लोबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी एक्सपीरियन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों पर आर्थिक धोखाधड़ी का खतरा 25 फीसद अधिक रहता है। एशिया-प्रशांत के दस देशों में किए गए सर्वे में सामने आया कि इस क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा गलत डाटा शेयर किया जाता है। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन लेन-देन में 24 फीसद भारतीयों के साथ धोखाधड़ी हुई है।

### क्या है

1. इलेक्ट्रॉनिक्स और यात्री सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां भले ही तेजी से अपने उपभोक्ताओं का डाटा एकत्र कर रही हैं और इससे मुनाफा भी कमा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे ज्यादा खतरा भी इन्हीं पर मंडरा रहा है।
2. देश के महज छह फीसद लोग ही अपने डाटा को सेवा प्रदाताओं से सुरक्षित रखते हैं। जापान में यह आंकड़ा आठ फीसद है, जो कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक है।
3. यह ऑनलाइन सर्वे एशिया-प्रशांत के दस देशों के बाजारों में किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
4. 50 फीसद भारतीय बैंक को बड़ी आसानी से डाटा उपलब्ध करा देते हैं। सबसे कम 30 फीसद लोग ब्रांडेड रिटेलर्स के साथ अपना डाटा साझा करने में सुरक्षित महसूस करते हैं।
5. 51 फीसद भारतीय बड़ी आसानी से अपना निजी डाटा विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों को मुहैया करा देते हैं।

### IPO और बायबैक के बदलेंगे नियम

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने को बोर्ड की बैठक में प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) समेत अधिग्रहण और शेयर बायबैक संबंधी नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी। इसके तहत राइट्स इश्यू के मामले में ड्राफ्ट लेटर की अनिवार्यता की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बैठक में पब्लिक और राइट्स इश्यू के मामले में थर्ड-पार्टी असाइनमेंट्स के नियमों में भी बदलाव समेत शेयर बाजारों के प्रमुखों की कार्यअवधि भी तय कर दी गई है। आइपीओ के फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव करते हुए नियामक ने एसएमई आइपीओ के लिए एंकर निवेशक की न्यूनतम निवेश राशि दो करोड़ रुपये तय कर दी है।

### क्या है

1. स्टॉक मार्केट की तरह ही सेबी ने डिपोजिटरीज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन में भी घरेलू और विदेशी इकाइयों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 15 फीसद तय कर दी गई है।

2. इसके साथ-साथ शेयर बाजारों और मार्केट इंटरमीडिएटरीज इंस्टीट्यूशंस के प्रमुखों का पांच वर्षों का अधिकतम दो कार्यकाल या अधिकतम 65 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है।
3. इसके अलावा सेबी ने नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) को कंपनीज एक्ट के तहत एक कंपनी के तौर पर मान्यता देने का भी फैसला किया।
4. नियामक ने कहा कि वह एनसीएफई में 30 फीसद हिस्सेदारी 30 करोड़ रुपये में खरीदेगा। सेबी के मुताबिक ये सभी बदलाव शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों और उनके निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आने वाले दिनों में अहम साबित होंगे।
5. नियामक ने बताया कि इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (आइसीडीआर) के दिशानिर्देशों में बदलाव को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है।
6. एक बयान में सेबी ने कहा कि ओपन ऑफर के मामले में ऑफर प्राइस में संशोधन के लिए समय-सीमा टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होने से एक कार्यदिवस पहले तक बढ़ाई गई है।
7. नियामक का कहना था कि ये सुधार मुख्य रूप से नियमों की भाषा की वजह से होने वाली परेशानियां दूर करने, गैरजरूरी प्रावधान खत्म करने और नियमों को कंपनीज एक्ट, 2013 के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
8. सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि बायबैक नियमों में बदलाव के तहत बायबैक अवधि की परिभाषा तय करने संबंधी प्रावधान भी शामिल रहेंगे।

### एसईजेड नीति पर गठित 'गणमान्य व्यक्तियों के समूह' ने पहली बैठक की

भारत की विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नीति के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 'गणमान्य व्यक्तियों के समूह' की पहली बैठक वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 22 जून, 2018 को आयोजित की गई। मंत्री महोदय ने इस समूह के सदस्यों से एसईजेड की पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर एसईजेड नीति को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव सुझाने का अनुरोध किया, ताकि पर्यावरण संबंधी जरूरतों से समझौता किए बगैर उद्योग में नियमों को हटाया जा सके।

क्या है

1. भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी इस समूह के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि आज सबसे बड़ी चुनौती रोजगारों का सृजन करना है और इस समूह का फोकस इस चुनौती से पार पाने पर होगा। उन्होंने कहा कि यह समूह वित्तीय प्रोत्साहनों के बजाय रोजगार आधारित प्रोत्साहन देने, संबंधित दायरे को नये सिरे से तैयार करने और मौजूदा प्रावधानों के लिए रियायत संबंधी अनुच्छेद शुरू करने से संबंधित सुझाव देगा।
2. इस समूह ने जुलाई, 2018 के मध्य में अपनी बैठक फिर से करने का निर्णय लिया है और वह अगस्त, 2018 के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा।

### IDBI-LIC सौदे से पहले ही पक्का की मंजूरी

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता आइडीबीआई बैंक में एलआइसी द्वारा अपनी हिस्सेदारी 51 फीसद पर पहुंचाने की कोशिश संबंधी खबरों को बैंक ने सिरे से खारिज कर दिया है। बैंक का कहना है कि इस बारे में अब तक उसके निदेशक बोर्ड में कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी तरफ बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एलआइसी को आइडीबीआई में अतिरिक्त पूंजी निवेश को मंजूरी भी दे दी है।

क्या है

1. मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी बीमा कंपनी किसी भी अन्य कंपनी में 15 फीसद से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती। ऐसे में कहा जा रहा है कि इरडा ने एलआइसी के लिए नियमों में ढील दी है।
2. अगर यह सौदा होता है, तो आइडीबीआइ में सावर्जनिक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) की नियंत्रक हिस्सेदारी हो जाएगी। इसके लिए उसे बैंक में 1,3000 करोड़ लगाने होंगे। वर्तमान में बैंक में एलआइसी की हिस्सेदारी 11 फीसद है।
3. शेयर बाजारों ने सौदे की चर्चा के बारे में बैंक से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में बैंक ने कहा कि एलआइसी द्वारा बैंक में 13,000 करोड़ तक निवेश किए जाने के बारे में उसके निदेशक बोर्ड में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है।
4. आइडीबीआइ लगातार बढ़ते फंसे कर्जों यानी एनपीए के चलते दबाव में है। मार्च तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 55,600 करोड़ रुपये के भारी-भरकम स्तर पर पहुंच गया था।
5. इस तिमाही में बैंक का शुद्ध घाटा 5,663 करोड़ रुपये रहा था। बैंक का बाजार पूंजीकरण करीब 23,000 करोड़ रुपये है, जबकि रियल एस्टेट एसेट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अनुमानित आकार 20,000 करोड़ रुपये है।

## विज्ञान एवं तकनीकी

### दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर

सुपर कंप्यूटर बनाने के मामले में जापान और चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम की है। इस सुपरपावर देश ने अब तक का सबसे ताकतवर कंप्यूटर 'समिट' लांच किया। अमेरिका के उर्जा विभाग की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए इसे अमेरिकी आइटी कंपनी आइबीएम ने बनाया है। यह विभाग के पिछले सुपर कंप्यूटर टाइटन से आठ गुना ज्यादा ताकतवर है। यह एक सेकंड में दो लाख ट्रिलियन (दो लाख लाख करोड़) गणनाएं करने में सक्षम है। इसका उपयोग उर्जा, एडवांस्ड मैटेरियल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए किया जाएगा।

क्या है

1. समिट न सिर्फ वैज्ञानिक मॉडल बनाने में सहायक होगा, बल्कि कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और वैज्ञानिक खोज को एक साथ ला सकेगा।
2. इसके जरिए शोधकर्ता इंसानी स्वास्थ्य, हाइ एनर्जी फिजिक्स, तत्वों की खोज समेत कई क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।
3. सुपरकंप्यूटर्स की कार्यक्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड (एमआइपीएस) की बजाय फ्लोटिंग-प्वाइंट ऑपरेशन पर सेकंड (फ्लॉप्स) में मापा जाता है।
4. ऐसे सुपरकंप्यूटर जो प्रति सेकंड क्वाड्रिलियन (दस लाख अरब) तक गणनाएं कर सकते हैं उनकी क्षमता पीटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। वहीं एक करोड़ गीगाबाइट मिलाकर एक पीटाबाइट बनता है।
5. 1980 में भारत अमेरिका से क्रे सुपरकंप्यूटर खरीदना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका ने कंप्यूटर के निर्यात से मना कर दिया।

6. इसके बाद 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने देश का पहला स्वदेशी सुपरकंप्यूटर परम 8000 लांच किया। जून, 2017 में देश के चार सुपरकंप्यूटर शीर्ष 500 कंप्यूटरों की सूची में शामिल थे। सीडैक उन्नत श्रेणी के सुपरकंप्यूटर बनाने पर काम कर रहा है।

### इस दिन सबसे करीब होंगे पृथ्वी और मंगल

आसमान में सितारों को निहारने के शौकीन लोगों को लाल ग्रह का बढ़िया नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2003 के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु के पास आ जाएगा। नासा के मुताबिक, ऐसा अगले महीने 27 जुलाई को होगा।

#### क्या है

1. अंतरिक्ष में मंगल, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे, जिसके चलते मंगल पृथ्वी के करीब होगा। इस दौरान सूर्य का प्रकाश मंगल पर पूरी तरह से पड़ने से इसे पृथ्वी से अच्छी तरह से देखा जा सकेगा।
2. तीनों ग्रहों का एक सीध में आना मंगल की कक्षा में कहीं भी हो सकता है। मंगल का सूर्य के करीब होने के दौरान जब ऐसा होता है, तो मंगल विशेष रूप से पृथ्वी के नजदीक आ जाता है।
3. साल 2003 में ऐसा लगभग 60,000 वर्षों में हुआ था।

### हीलियम-3 की खोज में ISRO

करीब एक वर्ष पूर्व चंद्रमा पर हीलियम खोजने की खबर को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सुर्खियों में था। उस समय यह चर्चा जोरों पर थी कि इसरो भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चंद्रमा पर हीलियम-3 की तालाश करेगा। हालांकि, बाद में इसरो ने इसका खंडन किया था। लेकिन एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है। इसरो अक्टूबर में एक रोवर और जांच (प्रोब) मिशन लॉन्च करेगा जो चांद की अछूती सतह पर मिट्टी और पानी के नमूनों को एकत्र करेगा, फिर इसे विस्तृत विश्लेषण और अनुसंधान के लिए वापस लाया जाएगा।

#### क्या है

1. वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हीलियम-3 कथित तौर पर 'स्वच्छतर' परमाणु संलयन के लिए एक मूल्यवान ईंधन है। ऐसे में इसरो ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चंद्रमा पर हीलियम-3 के खनन संबंधी संभावना तलाशने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यदि हीलियम-3 का पर्याप्त मात्रा में खनन और किफायती दरों पर परिवहन किया जा सके, तो यह पयूजन एक आकर्षक विकल्प भी हो सकता है।

#### आखिर क्या है हीलियम-3

1. हीलियम का यह आइसोटोप पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह सूर्य के द्वारा उसकी सौर वायु में उत्सर्जित होता है।
2. हमारा चुंबकीय क्षेत्र इसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है, चंद्रमा की ऐसी कोई ढाल नहीं है और इसलिए माना जाता है कि इसकी सतह सदियों से हीलियम-3 अवशोषित कर रही है।
3. चंद्रमा पर हीलियम-3 होने की पुष्टि विख्यात भूविज्ञानी हैरिसन शिमट ने 1972 में अपोलो 17 मिशन से चांद से लौटने के बाद की थी।
4. हीलियम-3 नाभकीय संलयन के लिए एक मूल्यवान और स्वच्छतर ईंधन है, जिसे धरती पर प्राप्त नहीं किया जा सका है।

2. इस बाबत दुनियाभर के कई निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष संगठन भी चांद पर खनन को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो एक उपयुक्त रिक्टर बनने तक हीलियम-3 और चांद पर मौजूद पानी के भंडारण के लिए खनन संबंधी संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि, जानकार कहते हैं कि दुनियाभर में कहीं भी ऊर्जा के उत्पादन में हीलियम-3 के इस्तेमाल की कोई तकनीक मौजूद नहीं है।
3. इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर के. सिवन का कहना है कि जिस किसी भी देश में चांद से इस स्रोत को लाने की क्षमता होगी वे ही इस प्रक्रिया पर अपना वर्चस्व कायम रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत इस प्रक्रिया का हिस्सा ही न हो, बल्कि इसका नेतृत्व भी करे, हम पूरी तरह से इस मिशन के लिए तैयार हैं।
4. भारत का यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के इसी तरह के चलाए जा रहे अभियान से काफी किरफायती है, जिसमें लगभग 800 करोड़ की लागत आएगी।
5. नासा के सलाहकार मंडल के सदस्य गेराल्ड कुसिंसकी की मानें तो चांद पर 10 लाख मिट्टिक टन हीलियम-3 उपलब्ध है, जिसका एक चौथाई हिस्सा धरती पर लाया जा सकता है।
6. विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में है। इससे 250 सालों तक वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। असीमित नाभिकीय ऊर्जा से परिपूर्ण हीलियम का यह आइसोटोप पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यह सूर्य के द्वारा उसकी सौर वायु में उत्सर्जित होता है।

### अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा पहला रोबोट क्रू

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए पहली बार किसी रोबोट को भेजा गया है। साइंस फिक्शन कॉमिक सीरीज से प्रेरित इस रोबोट को तड़के ड्रैगन कैप्सूल में रखकर स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट से भेजा गया। स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस यह निजी सहयोगी की भूमिका निभाएगा। अंग्रेजी में बात करने वाला यह रोबोट बास्केटबॉल के आकार का है, जो जर्मन अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर जस्ट को ISS पर प्रयोगों में सहयोग करेगा। इसका नाम क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कम्पैनियन यानी CIMON है।

क्या है

1. पांच किग्रा वजन वाले इस रोबोट के कोई हाथ या पैर नहीं हैं। यह एक आयताकार स्क्रीन है। स्क्रीन पर एक साधारण कार्टून फेस दिखाई देता है।
2. **CIMON** को एयरबस और **IBM** ने मिलकर विकसित किया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को उनके रोजाना के कार्यों को पूरा करने में रिपेयर इंस्ट्रक्शंस जैसी जानकारियों की प्रक्रिया को समझाएगा। यह वॉइस कमांड का अंग्रेजी में जवाब भी दे सकता है।
3. **CIMON** की परिकल्पना 1940 के दशक की साइंस फिक्शन कॉमिक सीरीज से प्रेरित है, जिसमें ब्रेन के आकार का रोबोट प्रफेसर सीमॉन एक अंतरिक्ष यात्री कैप्टन फ्यूचर को मदद करता है।
4. फिलहाल वैज्ञानिक इस पर निगरानी रखेंगे कि यह अलेक्जेंडर से कैसे संवाद करता है। आवाज के नमूने और तस्वीरों के माध्यम से अलेक्जेंडर को पहचानने के लिए CIMON को प्रशिक्षित किया गया है। ISS पर दोनों मिलकर कई मेडिकल प्रयोग भी करनेवाले हैं।
5. फिलहाल **CIMON** की क्षमता सीमित है। आगे चलकर इस तरह के रोबोट लोगों और मशीनों के बीच सामाजिक संवाद में भी मददगार साबित हो सकते हैं।

6. अभी जर्मनी के अंतरिक्ष यात्री लैपटॉप पर निर्देशों को पढ़ते हैं और उसके बाद स्पेस स्टेशन पर प्रयोग करते हैं। **CIMON** मौखिक तौर पर अलेक्जेंडर को स्टेप-बाइ-स्टेप निर्देश देगा। **ISS** पर दोनों मिलकर तीन से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे।

### भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा नया ग्रह

अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) एक नए ग्रह की खोज की है। इसका वजन पृथ्वी का 27 गुना और आकार छह गुना है। यह सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर चक्कर काट रहा है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह खोज सुपर नेपच्यून या सब-सैटर्न जैसे ग्रहों के संरचना तंत्र को समझने के लिहाज से बेहद अहम है।

क्या है

1. इस ग्रह को एपिक 211945201बी या के2-236बी के नाम से जाना जाएगा। इस खोज के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने हमारी सौर प्रणाली के बाहर ऐसे ग्रह की खोज की है जो तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।
2. यह शोध अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी के ऑनलाइन एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। मालूम हो कि अब तक सिर्फ 23 ऐसी ग्रह प्रणालियों (इस खोज समेत) की खोज हुई है।

### अब नैनो पार्टिकल्स से मात खाएगा एचआइवी

एड्स फैलाने वाले एचआइवी का नैनो पार्टिकल्स से पुख्ता 'इलाज' होने के सुखद संकेत मिल रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल्स साइंसेज (एनसीसीएस) ने संयुक्त शोध में 81 फीसद एचआइवी वायरस को मार डालने में कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिक अभी वायरस के पूरी तरह सफाए की कोशिश में जुटे हुए हैं। यह शुरुआती सफलता अभी परखनली

#### एचआइवी वायरस को ऐसे निष्प्रभावी बनाती है नैनो

1. एचआइवी वायरस के ऊपर जीबी120 ग्लाइको प्रोटीन होती है। यह बड़ी तेजी से बढ़ती है। इसका आकार 20 से 25 नैनो मीटर होता है। पुणे की लैब में वैज्ञानिकों ने 20 से 25 नैनो मीटर आकार वाले सर्कुलर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। दोनों को पानी भरे ग्लास में डाला गया।
2. जांच में पता चला कि नैनो पार्टिकल्स ने ग्लाइको प्रोटीन को पूरी तरह से कवर कर लिया है और अब ये उसे बढ़ने नहीं दे रहे। सामान्य पानी में डाले ग्लाइको प्रोटीन की ग्रोथ तेजी से होती रही। इस विधि में नैनो पार्टिकल्स को एचआइवी वायरस में किसी भी तरह से इंजेक्ट नहीं किया गया।
3. एचआइवी वायरस के खात्मे के लिए नैनो मैटेरियल का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर हुए सभी शोध मरीजों की उम्र बढ़ाने की जिद्दोजहद से जुड़े रहे हैं। रोग खत्म नहीं हुआ। हम रोग को खत्म करने पर काम कर रहे हैं।
4. हाइलीएक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एचएएआरटी) और बी-वैनम इसी तरह के शोध हैं। इनमें साइड इफेक्ट का अधिक खतरा है। बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी इस नैनो तकनीक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

परीक्षण में मिली है, लेकिन है बहुत बड़ी। उम्मीदों का दीया बनती दिख रही इस दवा का जल्द ही पशुओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, फिर इंसानों पर असर परखा जाएगा।

### क्या है

1. एएमयू में तैयार हुए नैनो पार्टिकल्स एएमयू के इंटरडिस्पलनरी नैनो टेक्नोलोजी सेंटर (आइएनसी) के डॉयरेक्टर प्रो. अबसार अहमद की अगुवाई में यहा की टीम ने कवक (फंगस) और कुछ पौधों से नैनो पार्टिकल्स तैयार किए।
2. शोधार्थी यह पता लगाने में जुटे हुए हैं कि ये पार्टिकल्स किन रोगों की दवा बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। सोना, चांदी, प्लैटिनम, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स आदि के नैनो पार्टिकल्स भी यहीं से देश के ख्यातिलब्ध पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल्स साइंसेज ( एनसीसीएस ) को भेजे गए थे।
3. एनसीसीएस में ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस ( एचआइवी ) के सफाए पर डेढ़ साल से शोध चल रहा है। प्रो. अबसार अहमद के मुताबिक परखनली में किए गए तमाम प्रयोगों के दौरान नैनो पार्टिकल्स के जरिये 81 फीसद एचआइवी को खत्म करने में कामयाबी मिल चुकी है। यह बहुत बड़ी बात है। इसने एचआइवी के सफाए की बड़ी राह दिखाई है। हालांकि, रिसर्च एक लंबी प्रक्रिया है और इसका लाभ जनता तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अभी मानकों की कसौटी पर नैनो पार्टिकल्स की सेफ्टी भी परखेंगे। सुरक्षित मिलने पर सरकार की मंजूरी से दवा का पहले पशुओं और फिर इंसानों में क्लीनिकल ट्रायल करेंगे।

### अंतरिक्ष का कचरा साफ करेगी यह महिला

जापान की रहने वाली 35 साल की मिकी इटो, जिन्होंने निहोन यूनिवर्सिटी से एयरो स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने के मिशन पर हैं। मिकी एस्ट्रोस्केल जापान की प्रेसिडेंट हैं। एस्ट्रोस्केल की शुरुआत कम खर्च में अंतरिक्ष में फैले कबाड़ को साफ करने के लिए की गई है। कंपनी ने फंडिंग से लगभग 53 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं। कंपनी का मुख्यालय सिंगापुर में है और कंपनी का रिसर्च एग्रीमेंट जापान की स्पेस एजेंसी के साथ है। एस्ट्रोस्केल और जापान की स्पेस एजेंसी मिलकर सेटेलाइट ईएलएसए-डी ( ELSA-d ) बना रहे हैं, जिसकी मदद से अंतरिक्ष से कचरा साफ किया जाएगा।

### क्या है

1. एस्ट्रोस्केल के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो संचार, एयरोस्पेस और अन्य कंपनियां संचार और पृथ्वी पर शोध के लिए कई सेटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में हैं।
2. ऐसे में यदि सेटेलाइट फेल हो जाता है, तो सर्विस प्रोवाइडर दूसरा सेटेलाइट भेजना चाहते हैं। लेकिन ऐसा तब ही मुमकिन हो सकता है जब पहले भेजे गए सेटेलाइट को उसकी जगह से हटाया जाए।
3. कंपनी का कहना है कि वह अपने साथ करार वाली कंपनियों के सेटेलाइट्स को टारगेट कर सकती है। और जरूरत पड़ने पर सेटेलाइट को वापस वातावरण में छोड़ा जा सकता है, जिससे वे खुद ही जलकर नष्ट हो जाए।
4. एयट्रोस्केल के अनुसार, उनका सेटेलाइट टूटे और नष्ट हुए सेटेलाइट्स को लेकर वातावरण में चला जाएगा। कंपनी के अनुसार इस काम में तकनीकी परेशानियां अंतरिक्ष में पहले से फैले कचरे से काफी कम हैं। कंपनी की योजना ईएलएसए-डी ( ELSA-d ) को 2019 में परीक्षण के लिए लॉन्च करने की है। इसके बाद 2020 में इसका व्यवसायिक तौर पर इस्तेमाल शुरू किया जा सकेगा।

### प्रॉजेक्ट 'ई-नेत्र'

यदि इलेक्शन कमिशन की प्लानिंग कामयाब रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव तक हर वोटर अपने स्मार्टफोन के साथ भ्रष्टचार के खिलाफ पुलिस की भूमिका में नजर आएगा। चुनाव आयोग की टीम एक मोबाइल ऐप्लिकेशन पर काम कर रही है। इस प्रॉजेक्ट का नाम है 'ई-नेत्र'। यदि कोई नेता अपने क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन (कैश या

शराब बांटना या भड़काने वाले भाषण देना ) करता है तो इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति उस नेता की शिकायत कर सकता है। इसके साथ उसे सबूत के तौर पर उसकी तस्वीर या विडियो भी अपलोड करनी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने यह जानकारी दी।

**क्या है**

1. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक ऐप्लिकेशन तैयार की है।
2. इस ऐप को पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर आने वाले चार राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम) के चुनाव में प्रयोग किया जाएगा।
3. कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चुनाव आयोग के लिए ऐसी ऐप्लिकेशन तैयार की थी, लेकिन यह चुनाव के कुछ समय पहले ही आ पाई। चुनाव तक इस ऐप को सिर्फ 800 लोगों ने डाउनलोड किया था। एक महीने के भीतर चुनाव आयोग नई ऐप्लिकेशन लॉन्च करने वाला है।
4. रावत ने भरोसा जताया कि लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुनाव आयोग की मदद करेंगे। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति उस वाक्ये की चुपचाप विडियो बना सकता है और सब्मिट कर सकता है। बगैर विडियो के भी शिकायत की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग को उसके लिए पर्याप्त सबूतों की जरूरत होगी।

**टीबी वैक्सीन से डाइबिटीज का भी इलाज संभव**

टीबी के इलाज के लिए जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है अब उससे टाइप-1 डाइबिटीज का इलाज भी संभव है। हाल ही अमेरिका में हुए रिसर्च के मुताबिक जो लोग टाइप-1 डाइबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए यह वैक्सीन ब्लड शुगर के लेवल को कम करने लिए काफी मदद करता है। टाइप 1 डाइबिटीज ऐसे डाइबिटीज होते हैं जिसमें पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता या फिर काफी कम बनाता है। शोध के मुताबिक चार हफ्तों के अंतराल पर लोगों दो-दो बार टीबी वैक्सीन यानि बीसीजी वैक्सीन दिए जाने के 3 साल बाद काफी सुधार देखा गया और उनका शुगर लेवल काफी कम हो गया था।

**क्या है**

1. इस शोध से जुड़े एक शोधकर्ता ने बताया कि जो लोग लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित हैं उन्हें इस वैक्सीन की मदद से शुगर लेवल को ठीक किया जा सकता है।
2. इस अध्ययन में करीब 282 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 52 लोग टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित थे, जिन्होंने बीसीजी वैक्सीन के ट्रायल में भी हिस्सा लिया। वहीं 230 लोगों के मेकनिस्टिक स्टडी के लिए ब्लड सैंपल लिए गए।
3. अध्ययन में सामने आया है कि इस डायबीटीज से पीड़ित जिन लोगों के बीसीजी वैक्सीन दिया गया जिसमें तीन साल के बाद ट्रीटमेंट के बाद HbA1c का लेवल 10 पसेंट कम पाया गया।

**शोधकर्ताओं ने तलाशे दूसरी धरती जैसे ग्रह**

अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुए शोध में विशेषज्ञों ने धरती जैसी विशेषता वाले दो ग्रहों की खोज करने का दावा किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है इन ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। इनका नाम केपलर- 62एफ और 186एफ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सौर मंडल के बाहर स्थित इनमें केपलर- 186एफ 500 प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकार में धरती जितना बड़ा है और अपने तारे का चारों ओर चक्कर लगा रहा है। धरती से



आकार में काफी बड़ा केपलर- 62एफ 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर मॉडल के जरिये इन दोनों ग्रहों की संरचनात्मक चीजों का आकलन किया है।

**क्या है**

1. इसके आधार पर उन्होंने यह पता लगाया है कि यह ग्रह अपनी धुरी पर कितना झुके हैं और इसके जरिये उसके समय की गणना कैसे की जा सकती है। ग्रहों का धुरी पर झुकाव उसके मौसम और वातावरण को तय करता है क्योंकि इससे उसके विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी का पता चलता है।
2. शोधकर्ताओं का कहना है कि केपलर-186 एफ का झुकाव जीवन की उत्पत्ति के लिहाज से मुफीद है। इसे धरती के समान समझा जा सकता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस ग्रह पर सामान्य मौसम होने के साथ ही यहां का वातावरण स्थिर होगा।
3. जॉर्जिया टेक असिस्टेंट और प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर गॉनाजी ली ने कहा कि हमारे सौर मंडल का एक और मंगल की स्थिति भी जीवन के लिहाज से मुफीद है। मगर उसका धुरी पर झुकाव सही नहीं होने के कारण वहां तापमान नियंत्रित नहीं रहता है। लाल ग्रह पर तापमान में शून्य से 60 डिग्री तक का अंतर आता है।

## विविध

### पूरी दुनिया योगमय

साल के सबसे लंबे दिन यानी 21 जून को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में करीब 55 हजार लोगों के साथ बैठकर योगासन कर किया। यह योग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफआरआई) के प्रांगण में किया गया। वहीं कोटा में बाबा रामदेव 2.5 लाख लोगों के साथ योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बाबा रामदेव के साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी हिस्सा लिया। 2 लाख लोगों को एकसाथ योग करते देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम कोटा में आई हुई थी। कोचिंग संस्थान के छात्रों आर्मी, पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में गांव के लोगों को योग के लिए बुलाया गया था। रामदेव पिछले 3 दिनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अभ्यास कर रहे थे।

**क्या है**

1. 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। आज चौथा योग दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय वेदों में वर्णित हजारों साल पुराना योग आज दुनियाभर में लोगों के तन-मन को स्वस्थ बना रहा है। दिसंबर, 2016 में योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है।
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए पहले ही संबोधन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया।
3. इसके लिए उन्होंने 21 जून तारीख सुझाई। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर, 2014 को 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके लिए 193 सदस्य देशों ने मंजूरी दी।
4. 193 सदस्य देशों में से 177 देशों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव पर भारत का समर्थन किया। पहली बार किसी प्रस्ताव पर इतने सह-प्रस्तावक बने।
5. पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश द्वारा कोई दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को महज 90 दिनों में पारित करके उसे लागू किया गया।

## अमेजन के सीईओ हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स

अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस 141.9 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। फोर्ब्स द्वारा 19 जून 2018 को जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में इस बात का खुलासा हुआ। बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हराकर पहला स्थान हासिल किया है।

क्या है

1. बेजोस की एक जून से संपत्ति पांच अरब डॉलर से अधिक बढ़ी है। वहीं, बिल गेट्स की संपत्ति 92.9 अरब डॉलर है। वॉरेन बफेट 82.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है।
2. बेजोस आधिकारिक तौर पर इस वर्ष की शुरुआत में दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे और उनकी ऑनलाइन रिटेलर अमेजन कंपनी एप्पल के बाद दूसरी सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी है।
3. फॉर्चून के पिछले लिस्ट के अनुसार, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की 2018 की लिस्ट में अमेजन 177.87 अरब डॉलर रेवेन्यू के साथ 8वें पायदान पर था।
4. जेफ हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने कई जगह जॉब की लेकिन उनका मन नहीं लगा। सबसे पहले उन्होंने अपना खुद का काम गैराज में शुरू किया बिजनेस चल पड़ा तो उन्होंने कंपनी को नाम देना का सोचा।
5. सबसे पहले उन्होंने कडाब्रा और फिर रेलेंटसेस डॉट कॉम जैसे नाम सोचे लेकिन बाद में साउथ अमेरिकी नदी अमेजन से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम अमेजन रखा जिस पर मुहर लग गई।
6. 2007 में कंपनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की और ऑनलाइन बिजनेस में उनकी कंपनी एक ब्रांड बन गई।

## दुनिया के हर 8वें व्यक्ति के पास है हथियार

19 जून 2018 को जारी स्मॉल आर्म्स सर्वे दुनिया में लोगों की असुरक्षा की भावना को बताने के लिए काफी है। संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर हर आठ लोगों में से एक के पास हथियार (आग्नेय अस्त्र) मौजूद हैं। 230 देशों में हुआ यह सर्वे बताता है कि दुनिया में कुल एक अरब छोटे आग्नेयास्त्र (पिस्टल, कार्बाइन या बंदूक) आदि हैं। इनमें से 85 प्रतिशत आम लोगों के पास हैं। शेष 15 प्रतिशत ही सरकारी संस्थाओं, सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं। अमीर देशों के नागरिकों का रुझान हथियार खरीदने की तरफ बढ़ा है।

क्या है

1. रिपोर्ट के लेखक आरोन कार्प के अनुसार नागरिक हथियारों में से 39.3 करोड़ केवल अमेरिका के पास हैं। यहां हर सौ लोगों पर 121 हथियार हैं। यह शीर्ष 25 देशों के कुल सिविलियन हथियारों से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका में गन कल्चर का आलम यह है कि यहां के नागरिक हर साल करीब 1.4 करोड़ हथियार खरीदते हैं।
2. सुरक्षा एजेंसियों के हथियारों की संख्या के मामले में अमेरिका पांचवें पायदान पर है। रूस, चीन, और भारत इससे ऊपर हैं। अमेरिका का हथियार प्रेम उसके लिए बड़ी त्रासदी बनता रहा है।
3. 2016 में हत्या के 64 प्रतिशत मामले इन हथियारों के कारण ही हुए। 1982 के बाद से यहां 90 सामूहिक गोलीबारी के मामले हुए हैं।
4. हर सौ नागरिकों पर हथियार रखने की संख्या के मामले में भारत, रूस, चीन टॉप 25 से बाहर हैं। जबकि पाकिस्तान का नंबर 20वां है।

## इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018

तीन वर्गों अर्थात परियोजना पुरस्कार, नवोन्मेषी विचार पुरस्कार एवं सिटी अवार्ड में 9 पुरस्कारों की इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत घोषणा की गई है, जिसे माननीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री द्वारा 25 जून, 2017 को आरंभ किया गया था। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष रूप से शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गंत्यात्मकता तथा टिकाऊ समेकित विकास के वर्गों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज गति प्रदर्शित करने के लिए सूरत स्मार्ट सिटी को सिटी अवार्ड के लिए चुना गया। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार शहरों, परियोजनाओं एवं नवोन्मेषी विचारों को पुरस्कृत करने, नगरों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 जून, 2017 को आरंभ किया गया था। योग्य प्रतिभागियों में केवल स्मार्ट सिटी शामिल थे जहां संबंधित यूएलबी/स्मार्ट सिटी एसपीवी को प्रस्ताव पेश करना था।

### क्या है

1. नवोन्मेषी विचार पुरस्कार किसी परियोजना/विचार, विशेष रूप से टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में उनके नवोन्मेषी, बॉटम-अप एवं रूपांतरकारी दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया जाता है।
2. इस वर्ग में संयुक्त विजेता अपने समेकित कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी) के लिए भोपाल तथा सुरक्षित एवं भरोसेमंद अहमदाबाद (एसएसएस) परियोजना के लिए अहमदाबाद रहे।
3. परियोजना पुरस्कार सात वर्गों में सर्वाधिक नवोन्मेषी एवं सफल परियोजनाओं को दिया जाता है, जो 01 अप्रैल, 2018 तक पूरी हो चुकी है।

### चुनी गई परियोजनाएं हैं-

1. 'अभिशासन' वर्ग के तहत पुणे से पीएमसी केयर
2. 'निर्मित पर्यावरण' के तहत पुणे से स्मार्ट प्लेस मेकिंग
3. 'सामाजिक पहलू' वर्ग के तहत एनडीएमसी एवं जबलपुर से स्मार्ट क्लास रूम, विशाखापत्तनम से स्मार्ट कैम्पस, पुणे से लाईट हाउस
4. 'संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था' वर्ग के तहत भोपाल से बी नेस्ट इन्व्यूबेशन सेंटर एवं जयपुर से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का संरक्षण
5. 'शहरी पर्यावरण' के तहत भोपाल, पुणे, कोयम्बटूर से पब्लिक बाईक शेयरिंग एवं जबलपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र
6. 'परिवहन एवं गंत्यात्मकता' वर्ग के तहत अहमदाबाद एवं सूरत से समेकित पारगमन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) एवं
7. 'जल एवं स्वच्छता' वर्ग के तहत अहमदाबाद से एससीएडीए के माध्यम से स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पुरस्कारों के तीन वर्ग हैं-

### नवोन्मेषी विचार पुरस्कार

1. 7 शहरी विषय वस्तुओं में आसाधारण नवोन्मेषण को सम्मानित करना
2. संबंधित विषय वस्तु (एक वर्ग से अधिक को समेकित करना)
3. इसका योगदान नगरों के सफल रूपांतरण में होना चाहिए
4. इसने बहु-हितधारक साझेदारी मॉडल एवं नागरिक सहयोग प्रदर्शित किया हो

### सिटी अवार्ड

#### मूल्यांकन

1. संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, एशियाई विकास बैंक एवं एनआईयू के अंतर्राष्ट्रीय/बहु-स्तरीय विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति ने नवोन्मेषण, प्रभाव एवं प्रतिकृति/अनुमापकता पर आधारित प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया।
2. सिटी अवार्ड पर फैसला 02 मई, 2018 (पुरस्कार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) को उनके पुरस्कार स्कोर एवं साप्ताहिक रैंकिंग पर नगरों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया।

1. नगर को कोई प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं है।
2. 'प्रोजेक्ट अवार्ड' एवं 'नवोन्मेषी विचार अवार्ड' के लिए विविध प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और मूल्यांकन के लिए परियोजना कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।

#### परियोजना अवार्ड

1. पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं (01 अप्रैल, 2018 तक)
2. 07 (सात) शहरी विषय वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए अलग पुरस्कार नीचे दिए गए हैं।

#### स्वदेश पैसा भेजने में भारतीय सबसे अग्रणी

दुनिया में जैसे भी आर्थिक हालात हों, प्रवासी भारतीयों की कमाई बड़ा हिस्सा स्वदेश भेजना नहीं भूलते। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2017 में प्रवासी भारतीयों ने 69 अरब डॉलर की भारी-भरकम रकम स्वदेश भेजी। यह रकम भारत के रक्षा बजट का डेढ़ गुना है। वहीं साल 2016 के मुकाबले 2017 में भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वदेश भेजी गई रकम में 9.5 फीसदी वृद्धि भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1991 से 2017 के बीच विदेशों से भारतीय द्वारा भेजी जानी वाला रकम 22 गुना तक बढ़ी है।

#### क्या है

1. भारतीय 1991 में महज 3 अरब डॉलर स्वदेश भेजते थे जो 2017 में बढ़कर 69 अरब डॉलर हो गई। वहीं वैश्विक स्तर पर प्रवासियों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली रकम 613 अरब डॉलर हो गई। भारत के बाद क्रमशः चीन, फिलीपींस, मेक्सिको, नाइजीरिया और मिस्र रहें जिनको प्रवासियों द्वारा सबसे ज्यादा पैसा भेजा गया।
2. प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे जानी वाली रकम में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केरल की रही। इंडियास्पेंड की रिपोर्ट 2016 के मुताबिक केरल की हिस्सेदारी 40 फीसदी रही। इसके बाद पंजाब (12.7 प्रतिशत), तमिलनाडु (12.4 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.7 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (5.4 प्रतिशत) रहें।
3. मौजूदा समय में 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। इनमें सबसे अधिक अमेरिका, सउदी अरब, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हैं।
4. विकासशील देशों को 2015 से लेकर 2030 तक करीब 6.5 खरब डॉलर का धनराशि (रिमिटेंस) प्रवासियों से मिलेगा। विदेशों से भेजे गए रकम में से आधा से अधिक ग्रामीण इलाकों में जाएंगे जहां गरीबी सबसे अधिक है।
5. प्रवासी लोगों के जरिए विदेशों से भेजा गया पैसा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह विदेशी निवेश से ज्यादा सुरक्षित व स्थायी भी होता है। यह धन विकासशील देशों में गरीबी हटाने और खुशहाली बढ़ाने का काम करता है।

#### महाराष्ट्र में पूरी तरह से प्लास्टिक बैन

महाराष्ट्र में 23 जून 2018 से प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था। अगर कोई भी दुकानदार या आम नागरिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि दूसरी बार में दस और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। साथ ही तीन महीने की जेल भी हो सकती है।

#### क्या है

1. अधिसूचना के मुताबिक, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनने वाले प्रोडक्ट को बैन किया गया है। इसमें प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल कप, थर्मोकोल की प्लेट, चम्मच, कांटे, चश्मा और कंटेनर शामिल हैं। इसके अलावा

- प्लास्टिक स्ट्रॉ, पाउच और पैकिंग वाली पन्नी भी राज्य के बैन में शामिल है। सजावट के लिए प्लास्टिक और थर्मालकोल का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है।
- राज्य सरकार ने इस साल मार्च में महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकॉल उत्पाद अधिसूचना जारी करने के बाद प्रतिबंध लागू किया था। सरकार ने निर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा स्टॉक का निपटान करने और प्लास्टिक की जगह कुछ और विकल्प के लिए तीन महीने का समय दिया था।
  - इस अधिसूचना को प्लास्टिक, पीईटी बोतल और थर्मालकोल निर्माता और खुदरा एसोसिएशन ने चुनौती दी थी। इस चुनौती में कहा गया था कि लगाए गए प्रतिबंध मनमाने हैं और कानूनी रूप से गलत हैं, इससे लोगों के घर चलाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।
  - सरकार ने दवाइयों, दूध, खाद्य पदार्थ, कृषि के काम में आने वाले उत्पाद जिन्हें डिस्पोज किया जा सकता है, उनके इस्तेमाल पर बैन नहीं लगाया है। जिन उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जाना है, उन पर बैन लागू नहीं है। कचरा निपटाने के लिए भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन नहीं लगाया गया है।
  - बारिश के दिनों में मुंबई में जलभराव की समस्या आम बात है। प्लास्टिक की वजह से नाले-सीवर जाम हो जाते हैं, जिससे बारिश का पानी निकल नहीं पाता है। मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने मुंबई में प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने के लिए करीब 250 इंस्पेक्टर भी नियुक्त किए हैं। देश में पहली बार आम आदमी पर प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर इतना सख्त बैन लगाया जा रहा है।

### आईआईटी में 'फीमेल ओनली पूल'

आईआईटी में इस बार लड़कियों को 14 फीसदी सीटों पर दाखिला मिलेगा। इसके लिए अलग से 'फीमेल ओनली पूल' बनाया गया है और अलग से कटऑफ भी तैयार की गई है। छात्राओं को पहले इस श्रेणी में सीट हासिल करने का मौका मिलेगा। इसमें असफल रहने पर जेंडर न्यूट्रल पूल में अवसर दिया जाएगा।

क्या है

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी में लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
- इसी के तहत यह फैसला लिया गया है। पिछले साल तक आठ फीसदी छात्राओं को प्रवेश मिल पाता था।
- लड़कियों का कोटा बढ़ाने के लिए 6% सीटें सृजित की जाएंगी। इससे लड़कों की सीटें कम नहीं होंगी।
- जो कोर्स शुरू हो रहे हैं, उसमें सभी 14% सीटें फीमेल ओनली पूल में रखी गई हैं।
- आईआईटी को यह व्यवस्था करनी है कि दोनों पूल में लड़कियों की संख्या 14 फीसदी तक पहुंच जाए।

### भारत के 25 सबसे गंदे शहरों में 19 पश्चिम बंगाल के

भारत के 25 सबसे गंदे शहरों में से उन्नीस पश्चिम बंगाल से हैं। वहीं गुजरात का भद्रेश्वर 500 शहरों की सूची में निचले पायदान पर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देश के 10 सबसे गंदे नगरपालिका क्षेत्रों में से सात पश्चिम बंगाल के हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के नगरपालिका क्षेत्र भी शामिल हैं। पिछले साल यूपी का गोंडा 434 रैंक के साथ सबसे गंदा नगरपालिका क्षेत्र था। इस साल गोंडा ने 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्रों में 228वां रैंक हासिल की है।

### क्या है

1. पश्चिम बंगाल ने इस साल पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लिया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि बंगाल के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, सेरामपुर, मध्यमग्राम, उत्तरी बैरकपुर, बांकुरा जैसे शहर कचरे के संग्रह, खुले शौचालय के चलते निचले पायदान पर हैं।
2. देश भर के 4203 नगरपालिका क्षेत्रों में यह सर्वे हुआ था। इस रिपोर्ट को 23 जून 2018 को पीएम मोदी ने जारी किया। इसके अलावा देश के सबसे गंदे चार राज्यों में पश्चिम बंगाल, नगालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा शामिल हैं।
3. इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया। इस श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः भोपाल और चंडीगढ़ ने पुरस्कार जीता।
4. स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में झारखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में अक्वल रहा। इस श्रेणी में महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे।

### देश की पहली ड्राइवर लेस कार

भोपाल में रहने वाले संजीव शर्मा ने देश की पहली चालक रहित रोबोटिक कार बनाई है। नौ साल की लंबी मेहनत के बाद वह इस कार को सड़क पर उतार पाए हैं। 2015 में पहली बार इस कार का सफल परीक्षण किया गया था। इस कार से हादसों की आशंका भी ड्राइवर वाली कारों की तुलना में 40 फीसदी कम होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि इंसान ड्राइविंग के दौरान एक सेकंड में अधिकतम 10 बार निर्णय ले सकता है, लेकिन ईजाद की गई सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के जरिये यह कार एक सेकंड में 40 बार निर्णय लेने की क्षमता रखती है।

### क्या है

1. आइआइटी रुड़की से पढ़े संजीव शर्मा ने रोबोटिक तकनीक से सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है। उन्होंने

#### ऐसे चलती है कार

1. कार का संचालन पूरी तरह तकनीक पर आधारित है। इसके लिए सॉफ्टवेयर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की लोकेशन देनी होगी। चलने की कमांड मिलने के बाद कैमरे फोटो लेते हैं और परसेप्शन तकनीक के माध्यम से गाड़ी के आसपास का नक्शा बनाया जाता है।
2. मोशन प्लानिंग से नक्शे के आधार पर कैसे, कितनी रफ्तार और कहां जाना है इसके लिए कंट्रोल कमांड जनरेट किए जाते हैं। डिजीजन मेकिंग एंड आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम स्थिति को भांपते हुए कार को आगे बढ़ाता है। इतना ही नहीं, भीड़ के आधार पर रफ्तार को भी कंट्रोल करता है।
3. इस तकनीक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वर्तमान स्थिति और दर्ज कराई गई लोकेशन के आधार पर शहर को परख लिया जाता है। इसी तरह हाईवे को समझ लिया जाता है।
4. शहरी क्षेत्र में 25 से 30 किलोमीटर और हाईवे पर 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलती है। संजीव बताते हैं कि इस तकनीक के जरिये उन्होंने 75 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार में बोलेरो गाड़ी को दौड़ाया है।
5. रोबोटिक तकनीक से चलने वाली यह देश की पहली कार है। जब कार के सामने बाधा आती है तो गाड़ी रुकती नहीं, न ही अवरोध दूर होने का इंतजार करती है, बल्कि अपना रास्ता बना लेती है। पहले जिन कंपनियों ने देश में ड्राइवर रहित कार को चलाया है उसमें सोनार सेंसर तकनीक का उपयोग किया गया। अवरोध आने पर यह तकनीक निर्णय नहीं ले पाती है कि रास्ता कैसे बनाया जाए।

स्वायत्त रोबोट्स नाम से कंपनी बनाकर स्टार्टअप के रूप में इसे शुरू किया है।

2. संजीव के मुताबिक इस तकनीक से टू-व्हीलर वाहन को छोड़कर ट्रक, कार, टैंकर्स जैसा हर वाहन चलाना संभव है। इसके लिए खर्च भी पांच से आठ लाख रुपये तक आता है।
3. संजीव इस तकनीक का उपयोग बॉर्डर पर टैंक ऑपरेटिंग और अन्य वाहन संबंधित गतिविधियों में करना चाहते हैं।
4. रोबोटिक तकनीक में सेल्फ ड्राइविंग के लिए कुल आठ कैमरों की आवश्यकता होती है। इसमें चार कैमरे सीसीटीवी और चार दूसरे कैमरे लगाए जाते हैं। साथ ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), मोटर, कंट्रोलर और तीन कंप्यूटर की आवश्यकता होती है।

### दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इस देश में

गरीबी में लगातार कमी के कारण भारत अब दुनिया में सबसे बड़ी गरीब आबादी वाला देश नहीं रहा है। अमेरिका के शोध संस्थान ब्रूकिंग्स ने अपने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। फर्म के ब्लॉग में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार 2018 की शुरुआत में ही, अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रही सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से नाइजीरिया, भारत से आगे निकल गया। यही नहीं, कांगो जल्द ही इस सूची में दूसरे नंबर पर आ सकता है।

क्या है

1. अध्ययन में कहा गया है कि अनुमान के अनुसार मई 2018 के आखिर में नाइजीरिया में लगभग 8.7 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। भारत में यह संख्या 7.3 करोड़ है।
2. नाइजीरिया में हर मिनट छह लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे में आते जा रहे हैं जबकि भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि ने इस अध्ययन पर कहा कि विकास पर उच्च खर्च और ऊंची वृद्धि दर से भारत में अति गरीबी तेजी से घटी है।
3. अध्ययन में 2030 तक दुनिया से गरीबी मिटाने के लक्ष्य को हासिल करने में संभावित दिक्कतों और चुनौतियों का भी जिक्र है। इसके अनुसार 2016 की शुरुआत में लगभग 72.5 करोड़ लोग अति गरीब थे।
4. लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रति सेकेंड 1.5 लोगों को गरीबी से निकालना था जबकि हमारी गति केवल 1.1 व्यक्ति प्रति सेकेंड की है। गरीबी उन्मूलन की गति धीमी होने के कारण हमारे लिए 2030 तक का लक्ष्य काफी मुश्किल होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित टिकाऊ विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक दुनिया से गरीबी मिटाना है।

### भारत में एक चौथाई लोग ही करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल

करीब दो दशक पहले शुरू हुए इंटरनेट के इस्तेमाल ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई तरह से बदलाव किया है। लेकिन देश की जनता के लिए इंटरनेट की पहुंच आज भी दूर की कौड़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर की वर्ष 2017 की रिपोर्टके अनुसार फिलहाल देश का एक चौथाई नागरिक ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इस रिपोर्ट में देश के युवाओं द्वारा स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

क्या है

1. रिपोर्ट बताती है कि भारत के चार में से एक वयस्क ही इंटरनेट विशेष अवसर पर इस्तेमाल करता है, जबकि करीब इतने ही लोगों के पास स्मार्टफोन भी है। स्मार्टफोन से मतलब ऐसे मोबाइल फोन से है, जिसमें इंटरनेट और एप चलाए जा सकें।

2. रिपोर्ट में शामिल विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले 39 देशों की सूची में भारत का स्थान निचले पायदान पर आता है। इस सर्वे में करीब 40 हजार लोगों को शामिल किया गया।
3. वयस्कों द्वारा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या के मामले में भारत सूची में शामिल सभी देशों से पीछे है। इस वर्ग में सबसे ऊपर अमेरिका है, जहां 80 फीसदी वयस्कों के पास स्मार्टफोन है, जबकि भारत में यह आंकड़ा महज 25 फीसदी है। वह कीनिया 32 फीसदी और नाइजीरिया 35 फीसदी से भी पीछे है।
4. रिपोर्ट बताती है कि भारत के वयस्क अभी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के इस्तेमाल में काफी पीछे हैं। भारत का 5 में से महज 1 नागरिक सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करता है। यह हालात तब है जबकि सर्वे में ज्यादातर सैंपल भारत के शहरी क्षेत्रों से लिए गए हैं।
5. देश में पीपुल रिसर्च द्वारा वर्ष 2016 में करीब 61 हजार घरों में कराए गए सर्वे के अनुसार, करीब 22 फीसदी घरों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा करीब 80 फीसदी इंटरनेट मोबाइल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
6. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में इंटरनेट विस्तार यह धीमी रफ्तार सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम की राह में रोड़ा साबित हो सकती है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट विस्तार सबसे अहम मसला है।
7. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल पर गरीबी या प्रति व्यक्ति आय का ज्यादा असर नहीं दिखता। क्योंकि, सर्वे में शामिल सेनेगल, घाना और नाइजीरिया में अपेक्षाकृत गरीबी ज्यादा है, जबकि स्मार्टफोन इस्तेमाल में ये सभी देश भारत से आगे हैं।

#### सबसे आगे चीन

1. 71 फीसदी वयस्क चीन में करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल
2. 70 फीसदी आंकड़ा है ब्राजील में इंटरनेट इस्तेमाल का
3. 25 फीसदी वयस्क ही भारत में करते हैं इंटरनेट का उपयोग
4. 15 फीसदी थी वर्ष 2013 में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या

#### एक तिहाई युवाओं के पास स्मार्टफोन

1. 35 फीसदी भारतीय युवाओं के पास ही स्मार्टफोन
2. 100 फीसदी युवा जर्मनी में रखते हैं स्मार्टफोन
3. 98 फीसदी युवा अमेरिका में स्मार्टफोन चलाते हैं
4. 96 फीसदी लोगों के पास स्मार्टफोन है चीन में

### स्विस बैंक में बढ़ा भारतीयों का पैसा

भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन 50 फीसदी बढ़ गया है। चार साल में पहली बार स्विस बैंक में जमा धन बढ़ कर पिछले साल एक अरब स्विस फ्रैंक (7,000 करोड़ रुपये) के दायरे में पहुंच गया है। यह आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। स्वित्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आयी है। इसके अनुसार भारतीयों द्वारा स्विस बैंक खातों में रखा गया धन 2017 में 50% से अधिक बढ़कर 7000 करोड़ रुपये (1.01 अरब फ्रैंक) हो गया। इससे पहले तीन साल यहां के बैंकों में भारतीयों के जमा धन में लगातार गिरावट आई थी। अपनी बैंकिंग गोपनीयता के लिए पहचान बनाने वाले इस देश में भारतीयों के जमाधन में ऐसे समय दिखी बढ़ोतरी हैरान करने वाली है जबकि भारत सरकार विदेशों में कालाधन रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है।

क्या है

1. स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के सालाना आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक खातों में जमा भारतीय धन 2016 में 45 प्रतिशत घटकर 67.6 करोड़ फ्रैंक (लगभग 4500 करोड़ रुपये) रह गया। यह राशि 1987 से इस आंकड़े के प्रकाशन की शुरुआत के बाद से सबसे कम थी।



2. एसएनबी के आंकड़ों के अनुसार भारतीयों द्वारा स्विस् बैंक खातों में सीधे तौर पर रखा गया धन 2017 में लगभग 6891 करोड़ रुपये (99.9 करोड़ फ्रैंक) हो गया। वहीं प्रतिनिधियों या धन प्रबंधकों के जरिए रखा गया धन इस दौरान 112 करोड़ रुपये (1.62 करोड़ फ्रैंक) रहा।
3. ताजा आंकड़ों के अनुसार स्विस् बैंक खातों में जमा भारतीयों के धन में ग्राहक जमाओं के रूप में 3200 करोड़ रुपये, अन्य बैंकों के जरिए 1050 करोड़ रुपये शामिल है। इन सभी मदों में भारतीयों के धन में आलोच्य साल में बढ़ोतरी हुई।
4. स्विस् बैंक खातों में रखे भारतीयों के धन में 2011 में इसमें 12%, 2013 में 43%, 2017 में इसमें 50.2% की वृद्धि हुई। इससे पहले 2004 में यह धन 56% बढ़ा था। एसएनबी के ये आंकड़े ऐसे समय में जारी किए गए हैं जबकि कुछ महीने पहले ही भारत व स्विट्जरलैंड के बीच सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान की एक नयी व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य काले धन की समस्या से निजात पाना है।
5. इस बीच स्विट्जरलैंड के बैंकों का मुनाफा 2017 में 25% बढ़कर 9.8 अरब फ्रैंक हो गया। हालांकि इस दौरान इन बैंकों के विदेशी ग्राहकों की जमाओं में गिरावट आई। इससे पहले 2016 में यह मुनाफा घटकर लगभग आधा 7.9 अरब फ्रैंक रह गया था।

### मद्र-छग में देश की सबसे ज्यादा बेनामी संपत्तियां

आयकर विभाग ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में अपनी छानबीन और छापामारी के बाद देश में सबसे ज्यादा 325 बेनामी संपत्तियों का पर्दाफाश किया है। मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान, मुंबई और गुजरात का नंबर है। विभाग ने जो प्रापर्टी अटैच की हैं, उनमें आईएएस अफसर, कारोबारी और कतिपय राजनेता भी हैं जिन्होंने दूसरों के नाम पर करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियां खरीदी हैं। संपत्तियों की मौजूदा कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। मद्र-छग में पिछले सवा साल की छानबीन में ये बेशकीमती संपत्तियां उजागर हुई हैं। सूत्रों का दावा है कि और भी मामले छानबीन में हैं, पुख्ता सबूत व साक्ष्य के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

क्या है

1. ये सभी कार्रवाई बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत की गई हैं। विभागीय अफसरों का कहना है कि नवंबर 2016 में अधिनियम आया, उसके दो-तीन महीने बाद दोनों राज्यों में बेनामी यूनिट की टीम ने अपना काम शुरू किया। सवा साल के नतीजे उत्साहजनक रहे।
2. अपने कालेधन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर निवेश करने वालों में आइएएस अधिकारी, कारोबारी और टेक्नोक्रेट ज्यादा हैं। कुछ कारोबारियों का राजनीतिक रसूख भी सामने आया है। पूर्व आइएएस अफसर अरविंद जोशी, एमए खान एवं सेवकराम भारती व टेक्नोक्रेट पीके सरैया के मामले भी हैं। कारोबारियों में संतोष रमतानी (सुरभि ग्रुप), पवन अहलूवालिया, एमवाय चौधरी, भाटिया एनर्जी (छग), अजय सोनी व नितिन अग्रवाल (छग), मनीष-हेमलता सरावगी एवं सुशील वासवानी जैसे नाम प्रमुख हैं।
3. विभागीय सूत्रों का कहना है कि शिकायतों, विभाग की खुफिया जानकारियों और छापे-सर्वे के दौरान मिले सुराग के आधार पर हुई पड़ताल में उक्त मामले सामने आए हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें हैसियत से ज्यादा शानो-शौकत का प्रदर्शन भी छानबीन का कारण बना। जांच के बाद टैक्स चोरी और नंबर दो की संपत्ति निवेश के अलावा आदिवासियों की जमीन फर्जी लोगों के नाम पर खरीदना भी दिखाया गया।
4. करीब 200 एकड़ जमीन, प्रीमियम बंगले और करीब डेढ़ दर्जन बेशकीमती प्लॉट भी अटैच किए गए हैं। इनमें अधिनियम की धारा 6ए और 6(1) के तहत कार्रवाई की गई है।

5. आयकर विभाग की बेनामी यूनिट ने सभी 325 संपत्तियों को प्रॉविजनल अटैचमेंट कर दिल्ली स्थिति एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ब्योरा भेजा है, जहां जल्द ही कानूनी औपचारिकताओं और निर्णय के बाद इन्हें राजसात कर दिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर बेनामीदार को धारा 53 के तहत एक से सात साल तक की सजा भी हो सकती है।

### विश्व बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट

जलवायु परिवर्तन से भारत के जीवन स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर देश के मध्य, उत्तर और उत्तर-पश्चिम राज्यों पर पड़ेगा। विश्व बैंक के मुताबिक, वर्ष 2050 तक यह गिरावट अधिकतम दस फीसद तक हो सकती है। इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य होंगे। इसके चलते कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का कहर होगा, जिससे जन जीवन के प्रभावित होने की आशंका है। विश्व बैंक ने भारत सहित दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन को लेकर जारी रिपोर्ट में यह बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव का असर भारत के जीडीपी पर पड़ेगा, जिसमें औसतन 2.8 फीसद तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे भारत का सामाजिक-आर्थिक तानाबाना भी प्रभावित होगा। इसके चलते देश को सूखे या पलायन जैसी स्थितियों का भी समाना करना पड़ सकता है।

#### क्या है

1. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका असर देश की करीब 60 करोड़ आबादी पर पड़ेगा। वहीं इसकी सबसे ज्यादा मार कृषि क्षेत्र पर पड़ेगी, जिसकी उत्पादकता में काफी गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।
2. इसकी चपेट में आने वाले दस सबसे प्रभावित जिलों में महाराष्ट्र के सात, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव व दुर्ग और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद होगा। यह सभी जिले अगले 32 सालों में देश के सबसे गरम स्थान होंगे। विश्व बैंक ने भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों को इसे लेकर उस समय सतर्क किया है, जब अकेले भारत के तापमान में सालाना डेढ़ से दो डिग्री तक की बढ़ोतरी हो रही है।
3. वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में भी इस बात पर चिंता जताई जा चुकी है। ऐसे में यदि इन बदलावों से बचाव के उपाय नहीं किए गए तो तापमान का यह स्तर 2050 तक आते-आते डेढ़ से तीन डिग्री तक बढ़ सकता है।
4. रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों के चलते सबसे ज्यादा गिरावट जिन राज्यों के जीवन स्तर पर पड़ेगा, उनमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा करीब दस फीसद, मध्य प्रदेश में 9.1 फीसद, राजस्थान में 6.4 फीसद, उत्तर प्रदेश में 4.9 फीसद, महाराष्ट्र में 4.6 फीसद, झारखंड में 4.6 फीसद, हरियाणा में 4.3 फीसद, आंध्र प्रदेश में 3.4 फीसद, पंजाब में 3.3 फीसद और चंडीगढ़ में 3.3 फीसद रहेगा।